सुविचार

बाहर की चुनौतियों से नहीं हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं

दैनिक रेवांचल टाइम्स

निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

■ वर्ष - 10 ■ अंक - 194 ■ मंडला, मंगलवार 29 सितम्बर 2026 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य-1 रूपये ■ विक्रम संवत् 2083 ■ www.revanchaltimes.com RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877

2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज, SC का केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ खास यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 प्रतिशत लोग इससे छूट प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी है और केंद्र व अन्य को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरूआत में यूपीआई के लिए एक नया फ्रेमवर्क घोषित किया, जिसके तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% का एमडीआर लगेगा।



सरकार का कहना है कि पर्सन-टू-पर्सन (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच) ट्रांजैक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के मुताबिक, ट्रांसफर की गई रकम चाहे कितनी भी हो सभी 'पर्सन-टू-पर्सन' ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा। सरकार ने कहा था कि सभी परसन 2 मर्चेंट (व्यक्ति-से-मर्चेंट) ट्रांजैक्शन में से लगभग 96 प्रतिशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमडीआर मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम का एक चार्ज है, न कि यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहकों से ली जाने वाली कोई फीस। बैंकों को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर न डालें, जबकि यूपीआई ऐप्स को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने से मना किया गया है।

सरकार की एक प्रेस रिलीज में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि बैंकों को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट एमडीआर चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें। प्रेस रिलीज में कहा गया है, "यूपीआई एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने से साफ तौर पर मना किया गया है।"

92 गवाहों का मुकर जाना चिंता की बात', सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में 22 आरोपियों को बरी करने पर सुको का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। यह याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति से जुड़े 2005 के कथित फेक एनकाउंटर मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सोहराबुद्दीन शेख के भाई नयाबुद्दीन शेख की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के 7 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही ठहराया गया था। बेंच ने संकेत दिया कि वह बरी करने से जुड़े चुनिंदा गवाहों के बयानों की जांच करेगी। सीजेआई ने कहा, "हम कुछ गवाहों के बयान देखना चाहेंगे। हम रिकॉर्ड नहीं मंगा रहे हैं। आपको जो भी तीन-चार बयान जरूरी लगते हैं, वे हमें दें। हम बरी करने के फैसले की जांच करेंगे।"

उज्जैन में शाही मस्जिद विवाद में फिर पथराव और लाठीचार्ज

महिला पुलिस अफसर घायल; 10 पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार





उज्जैन। एक तरफ जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराने को लेकर बवाल मच गया है। शहर काजी की अपील को न मानते हुए उपद्रवियों ने फिर से पत्थरबाजी की।

स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मामले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन प्रशासन और शहर काजी ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प : इससे पहले सोमवार सुबह प्रशासन जब बाधक हिस्सा हटाने पहुंचा तो उपद्रवियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान नारेबाजी हुई और कुछ समाजजन ने कार्रवाई का विरोध भी किया। उपद्रव करने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज का एक तबका आगर नाके पर जमा हो गया।



शहर काजी ने क्या अपील की : उज्जैन में शादी मस्जिद का हिस्सा हटाने को लेकर शहर काजी खलीकुर्रहमान ने कहा कि मस्जिद का मसला रात में ही हल हो चुका है। समाज के लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। बिना वजह बाजार में न खड़े हो और वहां न जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके पीछे हम वहां जाएं। जिस बात के लिए वादा हुआ है वो काम पूरा होना है। वो लोग अपने काम को कर रहे हैं। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाहों की वजह से घर से बाहर न निकलें।

उज्जैन के कलेक्टर ने क्या कहा : इसे लेकर उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि सभी धर्म-समुदाय के लोग स्वतः इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। उनके मकान, धर्मस्थल जो भी बीच में आ रहे हैं, उन्हें वे स्वतः हटा रहे हैं।

क्राइम ब्रांच की महिला टीआई को लगी चोट : शाही मस्जिद के पास बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे भीड़ ने हटाने की कोशिश की। उपद्रवियों की ओर से किए गए पथराव में क्राइम ब्रांच की महिला टीआई पुष्पा पांचाल को चोट लगी है।

क्या है मामला : कंठाल चौराहा से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद का करीब 10 फीट बाधक हिस्सा हटाया जाना है। सोमवार सुबह प्रशासन और? मुस्लिम समाज के बीच बातचीत के बाद समाजजन खुद बाधक हिस्सा हटाने पहुंचे। हालांकि इस दौरान नारेबाजी हुई और कुछ समाजजन ने कार्रवाई का विरोध भी किया। उल्लेखनीय है कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कंठाल चौराहा से गोपाल मंदिर तक 15 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है। शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा इस सड़क की निर्धारित सीमा में बाधक बन रहा था। इसी हिस्से को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।यह मार्ग महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर और शिप्रा तट को जोड़ता है। सिंहस्थ 2028 और धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए मार्ग चौड़ीकरण किया जा रहा है।

मन की बात में पीएम मोदी बोले- आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा



नई दिल्ली। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब स्पष्ट है। बालाकोट एयरस्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार-बार यह संदेश दिया है कि देश पर आतंकी हमला करने वालों को जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने यह बात रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ह्यमन की बातह्न में कही। उनका यह बयान 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ से ठीक पहले आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि उस कार्रवाई ने दुनिया को भारत की नई आतंकवाद-रोधी नीति का उदाहरण दिखाया। पीएम मोदी के मुताबिक, उस समय भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्होंने इसे लंबे समय से आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया बताया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। सरकारी और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उरी हमले में 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाने की कार्रवाई की थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पिछले एक दशक की प्रमुख आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के जरिए भारत ने यह संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जवाब का सामना करना पड़ेगा।

ईशा सिंह ने एशियन गेम्स में भारत को सिल्वर दिलाया: शूटिंग का 12वां मेडल

नई दिल्ली। शूटर ईशा सिंह ने जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत को सिल्वर दिलाया। वे महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में मामूली अंतर से गोल्ड से चूक गईं। सोमवार को फाइनल में ईशा को मेडल के लिए पांच शूट-ऑफ का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले सिल्वर के लिए मुकाबला जीता और फिर गोल्ड के लिए भी चुनौती पेश की। दूसरे शूट-ऑफ में ईशा ने पांच में से तीन शॉट मिस किए, जबकि चीन की शियाओ ने दो शॉट मिस किए। ईशा ने 580 अंक के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। जबकि, मनु मेडल इवेंट तक नहीं पहुंची। भारत मेडल टैली के 12वें स्थान पर है। उसके पास 39 मेडल हैं। इनमें 4 गोल्ड, 17 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज शामिल हैं।



उत्तराखंड में बर्फबारी से 136 पर्वतारोही फंसे:यूपी में बारिश से 8 नदियां उफान पर

नई दिल्ली। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से आदि कैलाश मार्ग समेत 86 सड़कें बंद हैं। इनमें चमोली की 21, नैनीताल की 18 और पिथौरागढ़ की 15 सड़कें शामिल हैं। बर्फबारी के बीच उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में 136 पर्वतारोही, ट्रैकर और सपोर्ट स्टाफ फंसे हैं। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं, नेपाल से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण और सुपौल के 23 गांवों में बाढ़ आ गई। बाढ़ से करीब 82 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। गोंडा और बदायूं में छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। आंधी-बारिश से पिछले 2 दिनों में 63 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में 2 गांवों के 1,400 परिवार प्रभावित हैं। राज्य के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में तीन दिनों से बारिश हो रही है।

फिल्म शुरू होने से पहले 22 मिनट तक दिखाए विज्ञापन, मल्टीप्लेक्स पर 75 हजार का लगा जुमार्ना

चेन्नई। हैदराबाद में फिल्म से पहले लंबे लंबे विज्ञापन दिखाना एक मूवी थियेटर को भारी पड़ गया है। हैदराबाद के एक उपभोक्ता आयोग ने मूवी थियेटर पर कॉमर्शियल विज्ञापनों और प्रोमोशनल कंटेंट की वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी होने के लिए 75 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया। यह पूरा मामला 20 जून 2025 का है। दरअसल एक 33 साल के व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ धनुष और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा के लिए रात 10:35 बजे के शो की टिकटें बुक की थीं । दोनों दर्शक 10:30 बजे ही थियेटर पहुंच गए। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी रात 10:52



मिनट तक सिर्फ विज्ञापन ही चलते रहे। शिकायत करने वाले व्यक्ति ने बताया कि इस देरी के कारण उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और वे उम्मीद से एक घंटा देर यानी सुबह 3 बजे घर पहुंचे। पीड़ित व्यक्ति ने इसे 'सेवा में कमी' बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 11 सितंबर, 2026 को इस पूरे मामले पर सुनवाई की और फैसला सुनाते हुए शिकायतकर्ता को सही ठहराया। आयोग ने माना कि जन-जागरूकता वाली स्वीकृत फिल्मों की अधिकतम सीमा दो मिनट तक ही हो सकती है। सिनेमाघर ने अपने व्यावसायिक फायदे के लिए दर्शकों का समय बर्बाद किया, जो अनुचित व्यापार व्यवहार में आता है। इस पूरे मामले पर सिनेमाघर प्रबंधन ने दलील दी कि विज्ञापन और ट्रेलर्स बिजनेस ऑपरेशन और जनसेवा का हिस्सा है, लेकिन आयोग ने इस बचाव को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर उपभोक्ता आयोग ने सिनेमाघर पर कुल 75 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया, आयोग ने 20 हजार रुपए मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए शिकायतकर्ता को बतौर मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया, वहीं 5 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के लिए, 50 हजार रुपए पेनल्टी के रूप में जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का भी निर्देश दिया। ताकि भविष्य में मूवी थियेटर ऐसी गलती न दोहराएं।

पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबलिंग को लेकर SC की FSSAI को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड के पैकेट के सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्तावित समय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब मामला सीधे तौर पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो प्राधिकरण इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करना चाहता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्राधिकरण की पहल अच्छी है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स
जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में
समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान
प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ
संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112
68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

बारिश से मक्का की तैयार फसल पर संकट, तुड़ाई में देरी और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। सितंबर के अंतिम दिनों में हो रही बारिश ने खेतों में तैयार मक्का की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश और खेतों में बनी नमी का असर मक्का की तुड़ाई पर पड़ने की आशंका है। किसानों के अनुसार खेतों में अधिक नमी रहने से फसल निकालने में परेशानी होगी और मौसम साफ होने तक तुड़ाई का काम प्रभावित हो सकता है।

बारिश के कारण तैयार मक्का के दानों में नमी बढ़ने की भी संभावना है। इससे दानों की चमक फीकी पड़ सकती है और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो खेतों में तैयार फसल को समय पर निकालना मुश्किल होगा। इसके अलावा आगामी मक्का की बुवाई भी प्रभावित होने और निर्धारित समय से आगे खिसकने की आशंका है। कृषि जानकारों के अनुसार जिन खेतों में मक्का पूरी तरह पकने की स्थिति में है, वहां किसान मौसम साफ होते ही तुड़ाई कर फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करें। बारिश से भीगी या अधिक नमी वाली फसल को जल्दबाजी में ढेर करने से बचना चाहिए। भंडारण से पहले फसल को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि दानों में नमी का स्तर कम हो सके।

जानकारों के मुताबिक अधिक नमी के साथ मक्का का भंडारण करने पर दानों के खराब होने और फफूंद लगने की आशंका रहती है। इससे फसल के वजन और गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को तुड़ाई के बाद फसल को पर्याप्त रूप से सुखाने और भंडारण स्थल को नमी से सुरक्षित रखने पर ध्यान देना होगा।

बारिश का असर आगामी मटर की फसल पर भी पड़ने की आशंका है। खेतों में लगातार नमी रहने के कारण मटर की बुवाई का समय आगे खिसक सकता है। इससे किसानों की फसल संबंधी तैयारियों का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। जिन किसानों ने मटर की बुवाई कर दी है, उन्हें भी खेतों की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।

मटर की फसल वाले खेतों में पानी का जमाव होने पर पौधों की शुरूआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। जलभराव वाले खेतों में फसल को नुकसान की आशंका अधिक रहती है। इसलिए किसानों को खेतों में पानी की निकासी की स्थिति पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है, ताकि फसल को लंबे समय तक पानी में रहने से बचाया जा सके। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम की स्थिति के अनुसार फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। फसल में किसी प्रकार के रोग या नुकसान के शुरूआती लक्षण दिखाई देने पर तत्काल कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने को कहा गया है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही किसी दवा या फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने की बात कही गई है।

किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम साफ होने का इंतजार करते हुए तैयार फसल की स्थिति पर लगातार नजर रखें और अनुकूल मौसम मिलते ही तुड़ाई तथा सुखाने की प्रक्रिया पूरी करें। इससे बारिश के कारण मक्का की गुणवत्ता में संभावित गिरावट और भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।

हाईवे पर चलती शिफ्ट कार में लगी आग, एएसआई और पत्नी सुरक्षित निकले



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम मौशम के पास हाईवे पर चलती शिफ्ट कार में अचानक आग लग गई। कार में दमोह जेल में एएसआई के पद पर पदस्थ प्रीतम सिंह अपनी पत्नी के साथ सवार थे। दोनों सिहोरा में आयोजित एक समारोह से लौटकर पान उमरिया स्थित अपने घर जा रहे थे। आग लगने के बाद कुछ ही देर में पूरी कार लपटों की चपेट में आ गई। बताया गया कि मौशम गांव के पास हाईवे पर पहुंचते ही कार में अचानक आग लग गई। चालक को जैसे ही आग का पता चला, कार रोककर दोनों सवार बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने वाहन को पूरी तरह घेर लिया और कार बुरी तरह जल गई। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कार में आग लगने की सूचना मिलते ही सिहोरा थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने तत्काल कार में सवार प्रीतम सिंह और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल वाहन के पहुंचने के बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। राहत की बात यह रही कि आग की चपेट में आने से एएसआई और उनकी पत्नी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को के अनुसार वह रात्रि गश्त पर थीं, इसी दौरान हाईवे पर कार में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और दोनों सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस की तत्परता से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के बाद आसपास मौजूद लोगों की भी मौके पर भीड़ जुट गई। हाईवे पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। दमकल की मदद से आग बुझाए जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और यातायात को सुचारू कराया गया। फिलहाल कार में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर वाहन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। वाहन में आग लगने की वजह जानने के लिए तकनीकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और एएसआई प्रीतम सिंह तथा उनकी पत्नी सुरक्षित हैं।



बरगी बांध के 17 गेट खुले, नर्मदा में 6136 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती आवक और जलस्तर को देखते हुए बांध प्रबंधन ने सुबह 11 बजे चार और गेट खोल दिए। इसके साथ ही बांध से पानी की निकासी के लिए खुले गेटों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। लगातार बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन द्वारा जल निकासी बढ़ाई गई है। बांध प्रबंधन के अनुसार सभी 17 गेटों से औसतन 2.36 मीटर की ऊंचाई से करीब 6136 क्यूमेक पानी प्रति सेकंड नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। आवक की स्थिति को देखते हुए गेटों से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है।

बांध प्रबंधन के अनुसार सुबह बांध का जलस्तर 423.06 मीटर दर्ज किया गया, जबकि बांध की निर्धारित जलस्तर क्षमता 422.76 मीटर है। निर्धारित क्षमता की तुलना में जलस्तर अधिक होने और पानी की आवक बढ़ने के कारण जल निकासी बढ़ाई गई है। अधिकारियों द्वारा जलस्तर और आवक के आंकड़ों की लगातार निगरानी की जा रही है। 17 गेट खुलने के बाद बांध से बड़ी मात्रा में पानी नर्मदा नदी में पहुंच रहा है। बांध के गेटों के सामने बने पुल के ऊपर से करीब 10 फीट तक पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए बांध क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जल निकासी की मात्रा को जलस्तर और आवक के अनुरूप बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। बांध प्रबंधन के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र में बारिश की स्थिति में बदलाव के साथ बांध में पानी की आवक भी घट-बढ़ सकती है। इसी आधार पर गेटों से पानी छोड़े जाने की मात्रा में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए जल निकासी की प्रक्रिया लगातार संचालित की जा रही है।

बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी के बहाव की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। बांध प्रबंधन द्वारा नदी में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा और जलस्तर की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले पानी की आवक पर भी निगरानी रखी जा रही है।

बांध के 17 गेट खुले होने के बाद बांध परिसर और आसपास के क्षेत्र में जल निकासी की स्थिति में बदलाव आया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण वहां पानी के तेज बहाव की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधन द्वारा मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निगरानी व्यवस्था बनाए रखी गई है। अधिकारियों के अनुसार बांध की स्थिति पूरी तरह जलस्तर और पानी की आवक पर निर्भर है। जलग्रहण क्षेत्र में बारिश जारी रहने की स्थिति में आवक बढ़ सकती है, जबकि बारिश कम होने पर आवक में कमी आ सकती है। इसी के अनुसार गेटों से पानी की निकासी को समायोजित किया जाएगा। बांध प्रबंधन जलस्तर, पानी की आवक और गेटों से हो रही निकासी की लगातार निगरानी कर रहा है। मौजूदा स्थिति में 17 गेटों से करीब 6136 क्यूमेक पानी प्रति सेकंड नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों द्वारा परिस्थितियों के अनुसार आगे की जल निकासी व्यवस्था तय की जाएगी।

हिरण नदी पुल पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कटंगी मार्ग पर हिरण नदी पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक बाइक से कटंगी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और 25 वर्षीय बृजेंद्र सिंह लोधी की मौके पर ही मौत हो गई। कटंगी पुलिस के अनुसार पौड़ी निवासी बृजेंद्र सिंह लोधी पिता रूप सिंह लोधी और हिनौता निवासी बुद्धू सिंह बाइक से कटंगी की ओर जा रहे थे। हिरण नदी के पुल पर पहुंचने के दौरान जबलपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बृजेंद्र सिंह के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, उसका साथी बुद्धू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। गंभीर हालत में बुद्धू सिंह को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद उसे मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस घायल की स्थिति और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। ट्रक की टक्कर के बाद हिरण नदी पुल पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा अचानक हुआ और बाइक सवारों को संभलने का मौका नहीं मिला। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि फरार ट्रक की पहचान की जा सके। पुलिस ने ट्रक के संभावित मार्गों की भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक बृजेंद्र सिंह के परिजनों में मातम छा गया। परिजन घटना की जानकारी मिलते ही मौके और अस्पताल की ओर रवाना हुए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कटंगी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ फरार ट्रक चालक की पहचान करने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर ट्रक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालक की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुरानी रंजिश में तलवारों से हमला, चार लोग घायल



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। गढ़ाफाटक मेन रोड स्थित श्री साईं गणेश उत्सव समिति के पास पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि 15 से 20 लोग तलवारों और अन्य हथियारों के साथ पहुंचे और घर के बाहर बैठे लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार कुछ समय पहले राजा रसगुल्ला वाली गली में कपिल सोनकर, राहुल सोनकर और उनके साथियों का मोहल्ले के कुछ युवकों से विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और मामला थाने तक पहुंचा था। इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी पुराने विवाद को लेकर तरुण सोनकर, कपिल सोनकर समेत कई लोग गढ़ाफाटक पहुंचे। आरोप है कि उनके हाथों में तलवारें और अन्य हथियार थे। हमलावरों ने घर के बाहर बैठे अहरवार परिवार के लोगों को निशाना बनाया और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में विपिन अहीरवार, दीपक अहिरवार, इमारती अहिरवार और अमित अहीरवार घायल हो गए। हमले के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही लार्डगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। घायलों की स्थिति और विवाद से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद की जानकारी जुटाई है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि घटना के समय मौके पर कितने लोग मौजूद थे और हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हमले में शामिल आरोपियों की पहचान करने के प्रयास कर रही है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गंभीरता से समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन की समीक्षा की गई। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में एएनसी पंजीयन की जानकारी ली गई। कलेक्टर श्री सिंह ने 55 प्रतिशत से कम एएनसी पंजीयन वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को एससीएन जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सीवियर एनिमिक गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन तथा उनमें पीएच के प्रबंधन की जानकारी ली तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों से भी गर्भवती महिलाओं की जानकारी लेकर उनके उचित प्रबंधन की भी समीक्षा की। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा, ब्लड बैंक तथा संचारी रोगों से संबंधित जानकारी भी ली गई। कलेक्टर श्री सिंह ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक गहलोत सहित स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

विश्व रेबीज दिवस पर लगे शिविर में 72 पशुओं को लगाया एंटी रेबीज टीका

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। विश्व रेबीज दिवस पर आज 28 सितंबर को आधारताल स्थित संभागीय पशु चिकित्सालय में पालतू एवं आवारा पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाने शिविर का आयोजन किया गया। रेबीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और क्षेत्र को रेबीज मुक्त बनाने के प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में 72 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं टीकाकरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को लेकर पहुंचे। क्षेत्र के आवारा कुत्तों का भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सकों ने नागरिकों को रेबीज के लक्षण, बचाव के उपाय और समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। शिविर में पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ जे पी शिव एवं उप संचालक डॉ ज्योति तिवारी की विशेष उपस्थिति रही।चिकित्सकों की टीम ने पशुओं की जांच कर पशुपालकों को आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी।

कलेक्टर सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न

दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए:- कलेक्टर सिंह



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, सेवा संकल्प अभियान, किसान पंजीयन और संबल योजना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, डीएफओ पुनीत सोनकर, अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, शैलेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह तथा सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सिंह ने आगामी दुर्गा पूजा में होने वाले धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले बड़े पंडालों की संख्या और स्थान की सटीक जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पंडालों में विद्युत व्यवस्था, ट्रेस एवं अन्य ढांचों की मजबूती तथा सुरक्षित सामग्री और विद्युत तारों के उपयोग पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, विद्युत, राजस्व, स्वास्थ्य एवं अस्पतालों से संबंधित शिकायतों का संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में आगामी सप्ताह आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत विभागवार लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही संबल योजना की समीक्षा करते हुए लंबित सहायता आवेदनों की जानकारी लेकर पात्र प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी धान उपार्जन को लेकर किसानों के पंजीयन की जानकारी लेते हुए सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिहोरा, मझौली, पाटन, पनागर और जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयन की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान ग्राम परासिया में खाद्यान्न वितरण में दाल और चावल की गुणवत्ता एवं निर्धारित मात्रा की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पर्यवेक्षक को वितरण की निर्धारित मात्रा की जानकारी ना होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सेवा संकल्प अभियान की आगामी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आधार सुधार, समग्र और केवाईसी जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा विभागीय स्टॉल लगाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार करें। कलेक्टर सिंह ने 7 अक्टूबर को प्रस्तावित सेवा ज्योति कलश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विधानसभा क्षेत्रवार रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए यात्रा मार्ग एवं अन्य व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर तय करते हुए जनपद स्तर पर बैठक कर योजना को अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने वन क्षेत्र से संबंधित लंबित कार्यों, विशेष रूप से वन अनुमति के कारण रुकी सड़कों एवं अन्य कार्यों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने 5 अक्टूबर को प्रस्तावित दिशा समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को अपनी पीपीटी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जराटीला में 4.50 लाख की गुणवत्ता विहीन पुलिया निर्माण पर उठे सवाल, सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत


सी एम हेल्पलाइन 181
जन हेतु -जन सेतु 181

शिकायत की स्थिति

दिनांक	शिकायत की स्थिति
27 Sep 2026	शिकायतकर्ता छोटेलाल जी द्वारा बताया गया कि ग्राम-जर्रा टोला , ग्राम पंचायत-जर्राटोला , ब्लॉक-अनूपपुर , जिला-अनूपपुर आवेदक का कहना है की पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है आवेदक द्वारा ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये। साढ़े 4 लाख की राशि स्वीकृत हुई है लेकिन कमजोर पुल बनाया जा रहा है जांच की जाये
25 Sep 2026	शिकायत निराकरण हेतु (ऐल1) अधिकारी है
25 Sep 2026	शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गयी है।


सी एम हेल्पलाइन 181
जन हेतु -जन सेतु 181

40743350 दिनांक - 25-09-2026	
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
पंचायती राज	
छोटेलाल अगरिया जी	
ग्राम-जर्रा टोला , ग्राम पंचायत-जर्राटोला , ब्लॉक-अनूपपुर , जिला-अनूपपुर	
XXXXXXX242, XXXXXXX242	
अनूपपुर	
क्षेत्र/ब्लॉक : अनूपपुर	

ग्रामीणों ने लगाए घटिया निर्माण के आरोप, जांच की मांग तेज

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जराटोला में लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये की लागत से निमार्णाधीन पुलिया को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। राजा राम पाण्डेय के घर के पास बन रही पुलिया के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से मौके पर जांच और निर्माण कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में स्वीकृत मापदंडों और मौके पर किए जा रहे निर्माण के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यदि निर्माण की तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में पुलिया की मजबूती और सुरक्षा को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। ग्रामीणों का दावा है कि एस्टीमेट में नींव की गहराई करीब 1.5 मीटर निर्धारित है, जबकि मौके पर लगभग 1 मीटर तक ही खुदाई किए जाने का आरोप है। ग्रामीणों ने इसकी वास्तविक माप तकनीकी अधिकारियों से कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार बेस में निर्धारित मोटाई के अनुरूप सामग्री नहीं डाली जा रही है। उनका आरोप है कि मौके पर बेस की परत काफी कम दिखाई दे रही है और उसके ऊपर गिट्टी डाली जा रही है। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और बेस की मोटाई की जांच की मांग की है। पुलिया में लगाए जा रहे सरिये को लेकर भी ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित माप के स्थान पर कम मोटाई के सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सीमेंट, रेत और अन्य सामग्री के मिश्रण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पुलिया पर भविष्य में भारी वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली का आवागमन होना है, इसलिए निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। पुलिया निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों की मांग है कि शिकायत पर केवल कागजी कार्रवाई न हो, बल्कि जनपद पंचायत के तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण की माप, नींव की गहराई, बेस की मोटाई, सरिये की गुणवत्ता, सीमेंट-रेत का अनुपात और कुल खर्च का भौतिक सत्यापन करें। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के भीतर एसडीएम अथवा जनपद पंचायत के तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच नहीं करते, तो वे सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपेंगे।

अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध अवस्था में युवती की हुई मौत जांच रिपोर्ट से होगा मौत का खुलासा



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जिला चिकित्सालय में इलाज कराने पहुंची 20 वर्षीय युवती सरिता प्रजापति पुत्री सुखलाल प्रजापति निवासी पोंडी चोड़ी की संदिग्धावस्था में मौत हो गई। युवती को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, इस दौरान परिजनों द्वारा जहर खाने की सूचना पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, हालांकि इस दौरान डॉक्टर ने युवती की बिगड़ती तबियत पर उसे स्थिर कर शहडोल मेडिकल कॉलेज के जाने की सलाह दी गई। लेकिन परिजन शहडोल ले जाने की बजाय जिला चिकित्सालय अनूपपुर में इलाज कराना चाह रहे थे। इसी दौरान अचानक युवती की तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की बात परिजनों से कही। जिस पर परिजन बिना पोस्टमार्टम शव ले जाने जिद्द करने लगे। इस पर पुलिस अधिकारी ने परिजनों को समझाते पोस्टमार्टम के लिए राजी कर शव को मचुर्री में रखवाया गए, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जाँच रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। डॉक्टर के अनुसार युवती के जहर खाने की आशंका बताई, लेकिन युवती के मुँह से न तो सल्फास या अन्य कीटनाशी दवा की गंध आ रही थी। घटना के दौरान घर में युवती, पिता के अलावा भाभी थी। माँ अपनी छोटी बहन के पास शनिवार को शहडोल मिलने गई थी। मृतिका की मौसी का कहना है की युवती को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, शनिवार की गांव में ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाते उसे इंजेक्शन दिलाई गई थी। दोपहर में युवती बाड़ी में बैठी थी, तबियत बिगड़ने पर जहर की आशंका में इलाज के लिए अस्पताल लेकर परिजन आए थे।

आबादी क्षेत्र में पहुँचा भालू, वन विभाग ने निगरानी के लिए विशेष टीम की तैनात, ग्रामीणों में दहशत का माहौल



दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर भालू के आबादी और खेतों के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम गिरवा और बेलिया के आसपास भालू के विचरण की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने तत्काल निगरानी शुरू कर दी है। विभाग की दो विशेष टीमें मौके पर तैनात की गई हैं, जो भालू की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। वहीं ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए गांवों में लाउडस्पीकर से मुनादी भी कराई जा रही है। वन विभाग के मुताबिक भालू मुख्य वन क्षेत्र से निकलकर खेतों और रिहायशी इलाकों के समीप विचरण कर रहा है। क्षेत्र में कृषि भूमि और आबादी एक-दूसरे से लगी होने के कारण मानव-वन्यप्राणी संघर्ष की आशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए वन अमले को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों और किसानों से कहा है कि वे खेतों की ओर अकेले न जाएं। विशेष रूप से शाम और रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें। भालू दिखाई देने पर उसे घेरने, उसके पास जाने या किसी तरह छेड़ने का प्रयास न करें। गौरतलब है कि केशवाही वन परिक्षेत्र में इस वर्ष भालू के हमले की दो घटनाओं में दो लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में जिले के अन्य इलाकों की तुलना में भालुओं की संख्या अधिक है। जंगल से सटे गांवों और खेतों में अक्सर इनके पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में विभाग ने ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

दो अलग-अलग मामलो मे पानी मे डूबने से व छत से गिरने से 2 युवकों की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। पुलिस चौकी फुनगा अंतर्गत दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत बम्हनी में दोपहर खेत में भरे पानी में 35 वर्षीय महेश बैगा की डूबने से एवं ग्राम पंचायत पाली में 21 वर्षीय दिनेश चौधरी की छत से गिरने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत बम्हनी में दोपहर खेत में भरे पानी में डूबने से महेश बैगा पुत्र भुत्ता बैगा, निवासी बम्हनी सुबह घर से गांव की जाने की बात कह निकला था। इसी दौरान गांव के सुनसान जगह के पास एक खेत में गांव के एक बुजुर्ग ने युवक के शव को देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फुनगा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां शाम पोस्टमार्डम करा परिजनों को सौंपा दिया। पति की मौत की सूचना पर पत्नी की तबियत बिगड़ गई, जहां पुलिस ने उसे स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया





है। पुलिस ने बताया कि मृतक खाने पीने का आदी था। प्रथम दृष्टया पांव फिसलने से खेत की मेढ़ पर गिरना और खेत में भरे पानी में गिरने और डूबने से युवक की मौत होना प्रतीत होता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी घटना पुलिस चौकी फुनगा के ही ग्राम पंचायत पाली में एक दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय युवक दिनेश पुत्र राकेश चौधरी की छत से गिरने से मौत हो गई। युवक शाम के समय घर की छत पर टहल रहा था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह छत से नीचे गिर गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी फुनगा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार पोस्टमार्डम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में सिर में गंभीर चोट के कारण मौत होने की बात कही। पुलिस शव परिजनों को सौंप मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने चोरी के प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 68 हजार रुपए बरामद

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। थाना चंदिया पुलिस द्वारा घर में रखी नगद राशि चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 68,000/- रुपये नगद बरामद किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 288/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। नंदलाल बैगा निवासी ग्राम देवरा, थाना चंदिया, जिला उमरिया द्वारा थाना चंदिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 23 सितंबर 2026 को उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी । परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार एवं पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। फरियादी के अनुसार घर में आवास योजना के प्राप्त हुये 60 हजार रुपए एवं अन्य कार्य हेतु पूर्व से रखे 30 हजार रुपए इस प्रकार कुल 90 हजार रुपए घर पर रखे हुये थे। दिनांक 23 सितंबर 2026 को लगभग दोपहर 12 बजे परिवार के सभी सदस्य पूजा



कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर में ताला लगाकर चले गए । शाम को वापस लौटने पर घर में रखे कुल 90,000/- रुपये चोरी होना पाया गया। मामले की रिपोर्ट पर थाना चंदिया पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया । विवचेना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन एवं संबंधितो से पूछताछ की गई, जिससे संदेही पुरुषोत्तम बैगा का नाम सामने आया, संदेही से प्रकरण के संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई । पूछताछ में आरोपी द्वारा घर में रखी पेटी का कुंदा तोड़कर उसमें रखे 90,000/- रुपये चोरी करना स्वीकार किया गया । पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से चोरी की गई राशि में से 68,000/- रुपये नगद बरामद किए गए । पूछताछ में आरोपी द्वारा शेष राशि खर्च करना बताया गया । आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय उमरिया के समक्ष पेश किया गया।



कोयला खदान में सुरक्षाकर्मी के साथ गाली-गलौज व मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। अमलाई थाना क्षेत्र स्थित रामपुर कोयला खदान में सुरक्षाकर्मी के साथ गाली-गलौज, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में अमलाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में फरार तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया है।

पुलिस के अनुसार सुरक्षाकर्मी अजय कुमार पटेल खदान परिसर में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान चार लोग खदान के अंदर पहुंचे और वहां मौजूद ट्रकों से कथित तौर पर अवैध वसूली करने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट कर दी। घटना में एसआईएसएफ के जवान के शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी आरोप है। घटना के बाद सुरक्षाकर्मी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर अमलाई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हीरामणि त्रिपाठी उर्फ बुग्गा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब सुनील तिवारी, सूरज तिवारी और राज द्विवेदी की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि सुरक्षा में तैनात एस आई एस एफ कंपनी के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई है। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं।

तीन दिवसीय प्रवास पर रहेंगे द्वारकापीठाधीश्वर शंकराचार्य, नर्मदा पूजन व रुद्राभिषेक सहित होंगे धार्मिक आयोजन



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। पवित्र नगरी अमरकंटक में आगामी 3 से 6 अक्टूबर तक पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर 1008 परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का प्रवास होगा। उनके आगमन को लेकर शंकराचार्य आश्रम सहित संत समाज एवं श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण है। प्रवास के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शंकराचार्य आश्रम के ब्रह्मचारी स्वामी नर्मदानंद ने बताया कि महाराज शंकराचार्य पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गुरुस्थान परमहंसी झोतेश्वर, गोटेगांव से अमरकंटक पधार रहे हैं। उनके आगमन पर आश्रम की ओर से विधिवत स्वागत-अभिनंदन किया जाएगा। इसके साथ ही पादुका पूजन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम होंगे। प्रवास में जगद्गुरु शंकराचार्य मां नर्मदा के उद्गम स्थल पहुंचकर दर्शन एवं पूजन करेंगे। इस दौरान ललिता सहस्त्रनाम,रुद्राभिषेक सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। प्रवास के दौरान वे अमरकंटक क्षेत्र के संत-महात्माओं से भेंट करेंगे तथा श्रद्धालुओं को सत्संग एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जगद्गुरु शंकराचार्य जी के अमरकंटक आगमन को धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल की पावन भूमि पर उनके प्रवास के दौरान आश्रम एवं आसपास के धार्मिक स्थलों में विशेष धार्मिक वातावरण देखने को मिलेगा। उनके दर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। शंकराचार्य आश्रम की ओर से प्रवास को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

पांच अधिकारियों पर 500-500 रुपये जुमार्ना

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। समय-सीमा की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित पांच अधिकारियों पर 500-500 रुपये की पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सीईओ जिला पंचायत ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हाउस, सीएम कार्यालय तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का तत्परता से जवाब दिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्रों का समय पर निराकरण कर जवाब भेजने तथा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

संपादकीय

चुनाव आयोग का पश्चाताप

चुनाव आयोग के अंतर्विरोध और आपत्तियों की खबर छपने के 48 घंटे में ही एहसास हो गया कि आयोग में कुछ गलत हो रहा है, जिसका निराकरण देशहित और लोकतंत्र-हित में होगा, लिहाजा मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई। तीनों की साझा उपस्थिति का चित्र भी जारी किया गया। बैठक की पहल किसने की और साझा संवाद की स्थिति कैसे बनी, यह जानना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बैठक के जरिए जो पश्चाताप किया गया और देश के मतदाताओं के पक्ष और हित में जो निर्णय लिए गए, वे बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। देश को चुनाव आयोग की बैठक और पश्चाताप का स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग की छवि निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक संवैधानिक संस्था की है, लिहाजा उस पर दाग नहीं आना चाहिए। अंतिम लक्ष्य लोकतंत्र और संविधान होना चाहिए, बेशक आपसी मतभेद और वैचारिक टकराव कितने भी हों! चुनाव आयोग की संपूर्ण बैठक में तय किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं अथवा किसी भी तरह की गलती, लापरवाही, अनदेखी, पूर्वाग्रह के कारण जिनके नाम मतदाता-सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे अब अपडेशन प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। जो पहली बार मतदाता बनने का दावा पेश करना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। खुद ईआरओ (इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) या बीएलओ आपके घर पर आकर दस्तावेज लेंगे। जिन मतदाताओं को नोटिस मिले हैं, वे भी ईआरओ और सहायक ईआरओ के कार्यालयों में न जाएं। खुद बीएलओ उनके घर आकर संबंधित दस्तावेज लेंगे और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे। उसके बाद किसी को भी अंतिम तौर पर मतदाता बनाने का काम पूरा हो सकेगा। नेट सॉफ्टवेयर पर जो गंभीर आरोप सामने आए थे कि मतदाता-सूची का केंद्रीकरण किया जा रहा है, उसकी जांच वरिष्ठ चुनाव उपायुक्त और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ करेंगे। अपडेशन पर हमारा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जिन 27 लाख से अधिक मतदाताओं को मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्या चुनाव आयोग उन पर भी पुनर्विचार करेगा? ट्रिब्यूनल जिस गति से न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, उसमें सांगोपांग न्याय में 12-14 साल का समय लग सकता है। क्या तब तक तार्किक विसंगति वाले लोगों के मताधिकार छिने रहेंगे? ट्रिब्यूनल के फैसलों में अभी तक करीब 93 फीसदी मतदाताओं के नाम सही पाए गए हैं। यह चुनाव आयोग के एसआईआर पर करारा तमाचा है। राजधानी दिल्ली में भी करीब 31-31 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं, क्या वे सभी 30 अक्तूबर (बढ़ाई समय-सीमा) तक अपने दावे और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे? क्या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और ईआरओ आदि नए सिरे से घर-घर जाकर कागजात इक्ठा करने और उन्हें अपलोड करने में सफल होंगे? यदि तय अवधि में यह काम नहीं हो पाता है, तो छूटे हुए मतदाताओं का क्या होगा? देश की बुनियादी चिंता मताधिकार की है, जो संवैधानिक अधिकार है। यदि वही छिन जाएगा या नजरअंदाज किया जाता रहेगा, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या हैं? अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि मजदूरों और बेघरों के मताधिकार के लिए हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह एहसास भी आयोग को हुआ है, अलबत्ता माता-पिता ही नहीं, दादा-दादी का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है कि वे पहले वाली मतदाता-सूची में थे अथवा नहीं। जो 18 वर्षीय नवयुवा पहली बार मतदाता बनने जा रहा है, उसे क्या पता होगा कि मतदाता-सूची में किन परिजनों के नाम शामिल थे? यह संदर्भ 2002 का पूछा जा रहा है। कइयों का जन्म बाद में हुआ है और ऐसे प्रशासनिक सवालों से वे अनभिज्ञ रहे हैं, लिहाजा फॉर्म 6 के साथ जोड़ा गया घोषणा-पत्र भी अनावश्यक और अवैध है। उसे सर्वोच्च अदालत ने कब स्वीकृति दी है, आयोग उसे भी स्पष्ट करे। बहरहाल चुनाव आयोग की संपूर्ण बैठक हुई है, यही सुखद खबर है। विपक्ष बेहद आक्रामक है, लामबंद हो रहा है, उससे सरकार और आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जनता चुनावों और एसआईआर के बहिष्कार की घोषणा करती, तो चिंतन करना लाजिमी होता, क्योंकि वही लोकतंत्र की आवाज है। यदि चुनाव आयोग दो आयुक्तों की आपत्तियों पर भी साझा स्पष्टीकरण दे, तो तस्वीर पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगी। चुनाव आयोग में आया यह अभूतपूर्व मोड देश की लोकतांत्रिक पक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। गौरतलब है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग को लेकर अब तक के सबसे तीखे प्रहार किए हैं।

ट्रंप से भारत के लिए बढ़ती टैरिफ चुनौतियां

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाल ही के महीनों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए आर्थिक-व्यापारिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमरीका के व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़े नीतिगत बदलावों के कारण उत्पन्न हुई है। हाल ही में 18 सितंबर को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले भारत-चीन समेत पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले बिल ह्यलिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026ह्ल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। यह कानून हस्ताक्षर किए जाने के 30 दिनों के भीतर प्रभावी होगा। यह कानून स्वचालित रूप से तुरंत टैरिफ लागू नहीं करता है। किस देश पर कितना टैरिफ लगाना है या राष्ट्रीय हित में किसे छूट देनी है, इसका अंतिम निर्णय अमरीकी राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए 24 सितंबर को अमरीका की यात्रा कर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नायाब तोहफा देते हुए कहा कि 10 जनवरी 2027 तक चीन पर 100 प्रतिशत या अन्य कोई नया टैरिफ लागू नहीं होगा। लेकिन भारत पर टैरिफ लागू होने की चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि अमरीका के इस नए टैरिफ कानून का प्राथमिक उद्देश्य रूस और ईरान के ऊर्जा स्रोतों से होने वाली राजस्व आय पर रोक लगाना है। इस कानून से भारत सहित दुनिया के कई देश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। रूस और ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत और चीन सबसे प्रमुख हैं।



निसंदेह भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक तरफ जहां रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, वहीं दूसरी ओर अमरीका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यदि अमरीका भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करता है, तो इससे भारतीय निर्यात को भारी झटका लग सकता है। ऐसे में अमरीकी संसद द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किए जाने और 100 प्रतिशत तक टैरिफ के प्रावधान पर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि 140 करोड़ से अधिक देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा और हित सर्वोपरि हैं, जिनसे कोई समझौता नहीं होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और ऐसे में भारत किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना, बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेगा। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाल ही के महीनों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए आर्थिक-व्यापारिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमरीका के व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़े नीतिगत बदलावों के कारण उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक आदेश के माध्यम से ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है और वीजा नियमों की जांच को पहले से अधिक सख्त कर दिया है। इस फैसले के तहत अमरीका के विदेश, श्रम और गृह सुरक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे वीजा आवेदनों को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि नियोक्ता ने हाल में अमरीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला न हो या भविष्य में छंटनी की योजना न बनाई हो। हालांकि, इस भारी भरकम शुल्क से उन विदेशी नागरिकों को राहत दी गई है जो पहले से अमरीका में छात्र वीजा एफ-1 पर रह रहे हैं या अपने मौजूदा वीजा का नवीनीकरण करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम मंत्री को 30 दिनों के भीतर श्रम स्थिति आवेदनों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले का सबसे गहरा असर भारतीय पेशेवरों और आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि कुल मंजूर एच-1बी वीजा में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी करीब 71 प्रतिशत है। 2025 में इस शुल्क के लागू होने के बाद से ही बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के पंजीकरण में करीब 92 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। यह नीति न केवल तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण अमरीका में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले भारतीय डाक्टरों को भी प्रभावित करेगी।इसी तरह गत 11 सितंबर को ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी और अन्य गैर-आप्रवासी वीजा धारकों की नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली 60 दिन की मोहलत को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में लागू नियम के अनुसार, नौकरी जाने पर विदेशी कर्मचारियों को अमरीका में रहकर दूसरी नौकरी खोजने, वीजा स्थिति बदलने या देश छोड? के लिए 60 दिन का समय मिलता है। यदि नया प्रस्ताव लागू होता है, तो नौकरी समाप्त होते ही कर्मचारी का वैध गैर-आप्रवासी दर्जा भी तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नई नौकरी मिलने पर भी कर्मचारी को अमरीका से बाहर जाकर दूतावास के जरिए पुनः आवेदन करना पड़ सकता है। इस कदम का सबसे बड़ा असर अमरीका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा, जो बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा पर निर्भर हैं। यह प्रस्ताव केवल एच-1बी तक सीमित नहीं है, बल्कि एल-1, ओ-1 और टीएन जैसी अन्य वीजा श्रेणियों पर भी लागू होगा। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग का तर्क है कि इससे कर्मचारी के रहने की वैधता और उसकी नौकरी के बीच सीधा संबंध बनेगा तथा प्रशासनिक बोझ कम होगा। फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। इस पर दो महीने तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। तब तक पुरानी 60 दिन की व्यवस्था लागू रहेगी। इसी प्रकार व्हाइट हाउस के ह्यऑफिस ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीह्ल की ह्यद ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैमह्ल रिपोर्ट में भारत समेत 40 से अधिक देशों पर चीन द्वारा अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध री-रूटिंग नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है।

भारत सरकार ने अमरीका की इस रिपोर्ट के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में सख्त कस्टम्स रूल्स और मजबूत कानून लागू हैं। इसके अतिरिक्त अमरीकी प्रशासन द्वारा आयातित जेनेरिक औषधियों पर चरणबद्ध तरीके से 1 अगस्त 2026 से नई शुल्क नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक (शुरूआती दो वर्षों के लिए) आयातित दवाओं को शुल्क से मुक्त रखा गया है, ताकि अमरीकी बाजार में दवा आपूर्ति बाधित न हो। इसके पश्चात, 1 अगस्त 2028 से 31 जुलाई 2029 तक दवाओं के मूल्य पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू किया जाएगा। अंततः 1 अगस्त 2029 के बाद इस शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह अमरीका की ओर से भारत के लिए बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत को अमरीका के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। एक संतुलित और औपचारिक व्यापार समझौता भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे औषधियां, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प पर अमरीकी शुल्क दरों को शून्य या न्यूनतम स्तर पर ला सकता है। लेकिन इस समय अमरीकी संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को रणनीतिक रूप से आगे बढ?ा होगा। अमरीका पर अत्यधिक निर्भरता घटाने के लिए लैटिन अमरीका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के गैर-पारंपरिक बाजारों में निर्यात का विस्तार करना आवश्यक है। साथ ही, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को शीघ्र लागू करते हुए व्यापारिक विविधता सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीद करें कि सरकार ट्रंप के टैरिफ और संरक्षणवादी चुनौतियों के बीच नई व्यापार साझेदारियों, निर्यात बाजारों के विविधीकरण और आर्थिक-वित्तीय नीतियों के जरिए देश के आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी।

राशिफल

मेष राशि :- कुटुम्ब में तनाव, क्लेश व अशांति, व्यर्थ का व्यय तथा प्रतिष्ठा हानि होगी।

वृष राशि :- इष्ट मित्र से सुख, अधिकारियों से मेल-मिलाप, समय लाभप्रद बना ही रहेगा।

मिथुन राशि :- अर्थ व्यवस्था अनुकूल हो, सफलता के साधन जुटायें तथा कार्य अवश्य ही बनेंगे।

कर्क राशि :- मनोवृत्ति उदार बनाये रखें, तनाव व क्लेश से हानि की संभावना बनी रहेगी।

सिंह राशि :- समय नष्ट न करें, व्यवसायिक गति रहे, असमंजस की स्थिति से बच कर चलें।

कन्या राशि :- आर्थिक योजना सफल हो, व्यवसायिक क्षमता अवश्य अनुकूल बनी रहेगी।

तुला राशि :- धन का व्यय, परिश्रम से हानि, मानसिक उद्विघ्नता से आप दूर चलें।

वृश्चिक राशि :- स्त्री कार्य से क्लेश व हानि, विघटनकारी तत्व आप को परेशान कर सकते हैं।

धनु राशि :- कुटुम्ब की समस्या सुलझे तथा धन का व्यय होगा, व्यर्थ भ्रमण आवश्य ही होगा।

मकर राशि :- अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न रहे, छोटे कार्य व्यय से कार्यगति मंद हो सकती है।

कुंभ राशि :- दैनिक कार्यगति में सुधार होगा, चिन्ताएह कम होंगी, सफलता के साधन जुटाएंगे।

मीन राशि :- मनोबल उत्साह वर्धक होवे तथा कार्यगति अनुकूल अवश्य ही बन जावेगी।

कमल के पत्तों की चाय किसी चमत्कार से कम नहीं है

आज के समय में खुद को फिट और स्वस्थ रखना बेहद जरुरी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अच्छा स्वास्थ्य ही खजाना है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और हर दूसरे दिन चाय के अलग-अलग फ्लेवर ट्राई करना पसंद हैं तो यह लेख आपके लिए है। जी, हां अगर आप खुद को फिट रखने और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ब्लैक टी, ग्रीन टी, फूलों से बनी चाय जैसे टी के कई फ्लेवर ट्राई करते हैं। हालांकि, इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अपने शायद ही पी हो। यह चाय खासतौर पर कमल के पत्तों से तैयार होती है। इस टी में विटामिन बी1, विटामिन सी जैसे गुण होते होते हैं। आइए जानते हैं कमल के पत्तों से बनी चाय के पीने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है।



संक्रमण से लड़ता

यहर रिसर्च में पाया गया है कि कमल की पत्तियों में कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को दूर करता है। इसलिए कमल की पत्तियों से बनीं चाय पीने से संक्रमण को रोका जा सकता है।

डायबिटीज में रखें कंट्रोल

कमल के पत्तों में मौजूद खास तत्व होता है जो ब्लड शुगर के बढ़ते हुए स्तर को कम करने में मदद करता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग नियमित रुप से कमल को डाइट में शामिल करते हैं उनमें डायबिटीज के लक्षणों में प्रभावी रुप से कमी देखी गई है।

सूजन और लालिमा दूर करने वाले गुण : कमल के पत्तों में खासतौर पर मौजूद कुछ तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन और लालिमा को दूर करता है। इसकी मदद से अर्थराइटिस, आईबीडी जैसी स्वास्थ्य समस्या होने पर शरीर की अंदरुनी व बाहरी हिस्सों में होने वाली सूजन को कम किया जा सकता है।

तनाव दूर होता है

कमल के पत्तों की चाय पीने से तनाव और चिंता दूर होता है। वहीं, यह तनाव से उत्पन्न मन में होने वाली घबराहट, हाथ-पैरों का ठंडे होने से बचाव करता है। अगर आप किसी तरह से तनाव से जूझ रहे हैं तो आप नियमित रुप से कमल की चाय का सेवन करें।

याददाश्त बेहतर करता है

मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कमल की चाय पीना काफी हेल्दी माना जाता है। यह आपके दिमाग को एक्टिव रखते हुए आपकी याददाश्त को बनाए रखने में मदद करता है।

कैसे बनाएं कमल की पत्तियों की चाय : - सबसे पहले आप कमल की पत्तियों को अच्छे से धो लें। अब एक पैन में गर्म पानी करें और उसमें कमल की पत्तियों को डालकर अच्छे से उबाल लें। अब इस पानी में चाय पत्ती डालकर उबाल आने दें। इसके बाद आपकी कमल की पत्ती की चाय बनकर तैयार है। इसे छानकर पी लें। आप चाहे तो इस चाय में स्वाद जोड़ने के लिए इसमें शहद भी मिला सकते हैं।

क्या इंडियन स्किन टोन के लिए सनस्क्रीन आवश्यक है?

स्किन के डॉक्टरों और सौंदर्य विशेषज्ञों को अक्सर भारतीय त्वचा के लिए सनस्क्रीन की आवश्यकता पर सवाल का सामना करना पड़ता है क्योंकि मेलेनिन यूवी विकिरण के खिलाफ कुछ सहज सुरक्षा प्रदान करता है, एक प्रचलित गलत धारणा है कि डार्क रंग की त्वचा वाले लोगों के लिए सनस्क्रीन आवश्यक नहीं हो सकता है। हालांकि, त्वचा देखभाल विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविकता कहीं अधिक छोटी है।

एचटी लाइफस्टाइल के एक्सपर्ट ने बताया है यह समझना महत्वपूर्ण है कि मेलेनिन सूरज की हानिकारक किरणों के खिलाफ कुछ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह त्वचा को नुकसान से पूरी तरह से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूवी विकिरण अभी भी त्वचा में प्रवेश कर सकता है, जिससे विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव जैसे सनबर्न, समय से पहले बूढ़ा होना और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, सभी भारतीय स्किन टोन मेलेनिन से समान रूप से सुसज्जित नहीं हैं। हल्के रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों में मेलेनिन कम हो सकता है और इसलिए वे सूरज की क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई और बाहर बिताया गया समय जैसे कारक यूवी जोखिम की तीव्रता को प्रभावित करते हैं, जो सूर्य की सुरक्षा की आवश्यकता पर और अधिक जोर देते हैं।'

इसके अलावा, यह गलत धारणा कि सनस्क्रीन भारतीय त्वचा के लिए अनावश्यक है, धूप से सुरक्षा के प्रति लापरवाही और उपेक्षा का कारण बन सकती है। लंबे समय में इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अधिक धूप में रहने से त्वचा कैंसर और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ सकता है। विभिन्न त्वचा रोगों की रोकथाम में सनस्क्रीन एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह यूवी विकिरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है, जिससे सनबर्न, फोटोएजिंग और त्वचा कैंसर का खतरा कम हो जाता है। त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने और धूप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए धूप से बचाव के अन्य उपायों, जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनना और तेज धूप के दौरान छाया की तलाश करना, के साथ-साथ सनस्क्रीन का नियमित उपयोग आवश्यक है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के दौरान फूड क्रेविंग्स को ऐसे करें हैंडल



आज के समय में लोग फिट बॉडी पाने के लिए तरह-तरह की डाइट फॉलो करते हैं। इन्हीं में से एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है। बता दें कि आज के समय में दुनिया के कोने-कोने में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो की जा रही है। इस फास्टिंग को वेट लॉस के लिए बेहतरीन डाइट मानी जाती है। इस फास्टिंग को फॉलो करने के दौरान आपको ईटिंग विंडो पीरियड फिक्स करना होता है। दिन के बाकी समय में आपको फास्टिंग करनी होती है। हालांकि लिमिटेड ईटिंग विंडो में आप सीमित मात्रा में खा पाते हैं और दिन भर अनहेल्दी स्नैक्स के सेवन से बच जाते हैं। जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है।

हालांकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, तो लगातार लंबे समय तक फास्टिंग करने से आपको भूख लगती है और तरह-तरह की फूड क्रेविंग्स होने लगती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी यह समस्या होती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान होने वाली फूड क्रेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं।

हाइड्रेट रहें : फास्टिंग पीरियड के दौरान आपको भरपूर पानी पीना चाहिए। कई बार हमारी बॉडी प्यास को भूख समझ लेती है, फिर तरह-तरह के फूड्स की क्रेविंग्स शुरू हो जाती है। उस दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी है। जबकि आपके शरीर में पानी की कमी होती है। इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे भूख लगने का एहसास भी कम होता है और पानी पाचन में भी आपकी मदद करता है और आपका पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। जिससे फूड क्रेविंग कम होती है। बता दें कि पानी के अलावा आप हर्बल चाय भी पी सकती हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें : जब आप ईटिंग विंडो में खाना खा रहे हैं, तो उसको स्मार्टली प्लान करके खाना चाहिए। जिससे आपको फास्टिंग पीरियड में भूख भी ना लगे। कुछ लोग इस दौरान अपना फेवरेट फूड आइटम खाना पसंद करते हैं। तो वहीं कुछ लोग सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करते हैं। बल्कि आपको प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स और फाइबर रिच संतुलित भोजन लेना चाहिए। इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। वहीं इन पोषक तत्वों को पचने में भी ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर लेवल को भी स्थिर करने में सहायता करते हैं।



सरंगापुर की टीम ने मारी बाजी, पारंपरिक वेशभूषा और लोकवाद्यों ने बांधा समां

खामखरेली में देर रात तक गूंजती रही शैला की थाप, 45 टीमों ने जमाया रंग



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी। सिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खामखरेली में मूलनिवासी परंपरागत जन जागृति समिति के तत्वावधान में भव्य शैला नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं पितृशक्ति ने सहभागिता करते हुए पारंपरिक संस्कृति और लोककला के इस उत्सव को यादगार बना दिया। प्रतियोगिता में करीब 40 से 45 शैला नृत्य टीमों ने हिस्सा लिया। विभिन्न ग्रामों से पहुंची टीमों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकवाद्य यंत्रों और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों के बीच पूरा परिसर शैला की थाप और लोकधुनों से गूंजता रहा। देर तक चले आयोजन में दर्शक भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। प्रतियोगिता में सरंगापुर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। टीम की शानदार प्रस्तुति पर उपस्थित दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि ईश्वरदयाल वरकड़े, कार्यक्रम संरक्षक महेश मार्सकोले, मंच संचालक भारत इनवाती एवं निर्णायक हजारी लाल उईके प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि एवं मार्गदर्शक गया प्रसाद कुमरे सहित मानक सिंह कुशराम, धर्मेंद्र इरपची, बहादुर सिंह, राजा उईके, मेर सिंह परते, सियाराम, संदीप उईके, बबलेश ठाकुर, राजू परते एवं दशरथ काकोदिया सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।

नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की पहल

आयोजकों ने कहा कि शैला नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पारंपरिक लोकसंस्कृति और विरासत की पहचान है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की लोककलाओं को मंच मिलने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलता है। खामखरेली में आयोजित शैला नृत्य प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों की टीमों की सहभागिता ने ग्रामीण अंचल की सांस्कृतिक एकता और लोककला के प्रति उत्साह को सामने रखा। आयोजन ने क्षेत्र में पारंपरिक कला एवं संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया।

जनसंवाद और योजनाओं की जमीनी स्थिति जानना भी उद्देश्य, क्या निर्माण कार्यों की हकीकत तक पहुंचेगी यात्रा?

सेवा संकल्प यात्रा का बंडोल में स्वागत, बच्चों को बांटे वस्त्र



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी-ह्यसेवा संकल्प अभियानह्न के तहत जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की भावना के साथ बड़नगर से वाराणसी के लिए निकली सेवा यात्रा का बंडोल पहुंचने पर आंगनवाड़ी भवन परिसर में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, संतोष अग्रवाल सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सेवा गतिविधियों के साथ आमजन से संवाद स्थापित करना, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, हितग्राहियों से चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानना तथा स्वच्छता, पौधारोपण, गौसेवा, युवा एवं वृद्धजन संवाद जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। बंडोल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने आंगनवाड़ी केंद्र के नन्हे-मुन्ने बच्चों को वस्त्र वितरित किए। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों की जानकारी ली।

स्वागत के साथ विकास कार्यों की हकीकत देखने की भी जरूरत

यात्रा का उद्देश्य जब आमजन से संवाद और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानना है, तो सवाल यह भी है कि क्या यात्रा जिन क्षेत्रों से गुजर रही है, वहां भाजपा शासनकाल में स्वीकृत राशि से कराए गए निर्माण एवं विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति भी देखी जाएगी? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल, आंगनवाड़ी भवन सहित विभिन्न सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, अधूरे कार्यों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में सेवा संकल्प यात्रा जनप्रतिनिधियों के लिए केवल स्वागत कार्यक्रमों में शामिल होने के बजाय मौके पर पहुंचकर इन कार्यों और स्थानीय जरूरतों को देखने का अवसर भी बन सकती है। सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए राशि जारी करने के बाद उसका उपयोग किस तरह हुआ, निर्माण की गुणवत्ता कैसी है और संबंधित सुविधा का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं—इन सवालों की जमीनी पड़ताल यात्रा के घोषित जनसंवाद के उद्देश्य को और सार्थक बना सकती है। अब देखना होगा कि सेवा संकल्प यात्रा बंडोल सहित अपने मार्ग में लोगों की समस्याओं, जरूरतों और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति तक पहुंचती है या स्वागत-सत्कार, निरीक्षण और औपचारिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रह जाती है।

गौशाला या गौवंश का कब्रिस्तान? मारबोडी में रोज मर रही गायें!

200 गड्ढे पड़े कम, ग्रामीणों का आरोप—गंदगी, भूख और बदइंतजामी के बीच गौवंश की मौत का सिलसिला जारी, शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार बेखबर



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- ग्राम मारबोडी की गौशाला में गौवंश की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में पर्याप्त साफ-सफाई, चारा-पानी और उपचार की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगातार गौवंश की मौत हो रही है। गौशाला परिसर में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा होने की बात भी सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला की स्थिति को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। स्थिति यह है कि गौवंश की मौत का सिलसिला थमने के बजाय लगातार जारी बताया जा रहा है। **जल रोको अभियान के गड्ढे बने मृत गौवंश को दफनाने का स्थान-** ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जल रोको अभियान के तहत करीब 200 गड्ढे खोदे गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन गड्ढों में बड़ी संख्या में मृत गौवंश को दफन किया जा चुका है। अब स्थिति यह बताई जा रही है कि गड्ढे कम पड़ने लगे हैं, लेकिन गौवंश की मौतें कम नहीं हो रही हैं।ग्रामीणों का सवाल है कि यदि गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, पानी, उपचार और साफ-सफाई की व्यवस्था है तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में गौवंश की मौत क्यों हो रही है? मृत पशुओं की संख्या, उनकी मृत्यु के कारण और गौशाला में उपलब्ध व्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।

जिम्मेदारों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

गौशाला संचालन में कौन जिम्मेदार है, पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच कौन करता है, प्रतिदिन कितनी मात्रा में चारा उपलब्ध कराया जाता है, पानी की क्या व्यवस्था है और मृत गौवंश के निस्तारण का रिकॉर्ड क्या है—इन सभी बिंदुओं को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि यदि गौशाला में गौवंश की देखभाल नहीं हो पा रही है तो ऐसी व्यवस्था को जारी रखने का क्या औचित्य है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मौके का वरिष्ठ अधिकारियों से निरीक्षण कराया जाए और गौशाला की पूरी व्यवस्था की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।

1000 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में 7 और अधिक श्रमिक वाले संस्थानों में 10 तारीख तक भुगतान अनिवार्य

श्रमिकों को समय पर वेतन देना होगा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले में कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में न्यूनतम वेतन एवं देय पारिश्रमिक का भुगतान करना नियोजकों के लिए अनिवार्य होगा। सहायक श्रम पदाधिकारी सिवनी ने बताया कि श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर के निदेर्शानुसार शासकीय विभागों, विश्वविद्यालयों, निगमों, मंडलों सहित संबंधित संस्थानों को श्रम कानूनों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 के तहत एक हजार से कम श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित करने वाले औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करना अनिवार्य है। वहीं एक हजार से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना जरूरी है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर वेतन भुगतान नहीं करने अथवा श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहायक श्रम पदाधिकारी ने सभी नियोजकों से अपील की है कि वे श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन एवं अन्य देय पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करें और श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करें।

सेवा सेतु कार्यक्रम में छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं की दी जानकारी

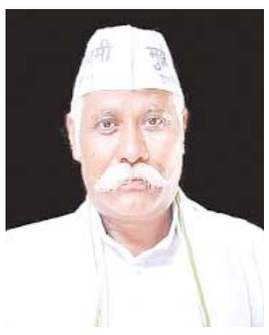


दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निदेर्शानुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान-2026 के कैलेंडर अनुसार ह्यसेवा सेतु-सरकार आपके द्वारह्न कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश सरवैया के संरक्षण तथा कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती अलका उईके के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डॉ. मुहम्मद राशिद खान ने छात्राओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं विद्यार्थी हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, गांव की बेटी, प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति, आवास योजना, मेधावी छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं के उद्देश्य एवं पात्रता के संबंध में छात्राओं को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौरान छात्राओं को योजनाओं के लिए आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया भी समझाई गई। साथ ही आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखने और समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव तथा ह्यविकसित भारत यंग लीडर डायलॉग-2027ह्न की जानकारी भी दी गई। इसके अंतर्गत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सहभागिता का अवसर दिया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में ह्यविकसित भारत क्विजह्न का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने माय भारत पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर क्विज में सहभागिता की तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

तूफान से मक्का प्रभावित, कुरई में बोवनी बाधित और केवलारी में माहू का प्रकोप

कलेक्टर से की तीन सूत्रीय मांग

फसल नुकसान पर आप ने की तत्काल सर्वे और राहत की मांग



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले में मौसम की मार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सिवनी विकासखंड में 18 सितंबर को आए तूफान से मक्का की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं कुरई में लगातार बारिश से कई स्थानों पर धान की बोवनी प्रभावित होने तथा केवलारी में धान की फसल पर माहू के प्रकोप की शिकायतें सामने आई हैं।

महागांव, लामार और ज्योति क्षेत्र के किसानों ने फसल नुकसान के वीडियो और आवेदन प्रशासन को सौंपकर सर्वे एवं राहत की मांग की है। क्षेत्र के सरपंच कमलेश पटेल सहित किसानों द्वारा प्रशासन का ध्यान नुकसान की ओर आकर्षित कराया गया है। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह सनोडिया ने कलेक्टर से जिले के सभी विकासखंडों में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर तत्काल सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों ने बीज, खाद, दवा और मजदूरी पर पूंजी लगाई है और फसल खराब होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

आप ने रखी तीन सूत्रीय मांग

सनोडिया ने प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने, पात्र किसानों को फसल बीमा की राशि का शीघ्र भुगतान कराने और कृषि ऋण माफी के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तूफान, बारिश से बोवनी प्रभावित होने और फसल में बीमारी से हुए नुकसान का अलग-अलग वास्तविक आकलन किया जाए। उनका कहना है कि सर्वे और राहत की प्रक्रिया में देरी से किसानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। सनोडिया ने कहा कि किसानों को आश्वासन के बजाय समय पर राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि किसानों की समस्याओं को पार्टी जिला एवं शासन स्तर पर उठाएगी।

फतेसिंग पटेल को कार्यकारी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती पर दिया जोर

रामजी चंद्रवंशी बने जिला गौली समाज के जिलाध्यक्ष



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिला गौली समाज की जिला स्तरीय बैठक में रामजी चंद्रवंशी को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं फतेसिंग पटेल (लामटा वाले) को कार्यकारी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में जिलेभर से पहुंचे समाज के वरिष्ठजन, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में छपारा, केवलारी, सुनवारा, गणेशगंज, भोमा, गोपालगंज एवं सिवनी सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। उपस्थितजनों ने सामाजिक एकता बनाए रखने तथा जिले के सभी क्षेत्रों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया।

शिक्षा और युवाओं की भागीदारी पर जोर

बैठक में समाज में शिक्षा के प्रसार, युवाओं की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक जागरूकता तथा संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने और सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रामजी चंद्रवंशी से समाज के लोगों ने संगठन को नई दिशा देने तथा जिलेभर के सामाजिक बंधुओं को एक मंच पर जोड़ने की अपेक्षा व्यक्त की। जिला संगठन की शेष कार्यकारिणी का गठन आगामी दिनों में किया जाएगा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पृथक रूप से जारी किए जाने की बात समाज की ओर से कही गई है।

SIR और मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा जिलाध्यक्ष का पलटवार

वोट चोरी के आरोप हैं तो प्रमाण सामने रखे कांग्रेस : मीना बिसेन



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना संभव है, लेकिन गंभीर आरोपों के साथ ठोस तथ्य और प्रमाण भी सामने रखे जाने चाहिए। मीना बिसेन ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ह्यवोट चोरीह्न का आरोप लगा रहे हैं। यदि उनके पास मतदाता सूची में अनियमितता या चुनाव परिणाम प्रभावित होने के प्रमाण हैं तो उन्हें बूथवार और तथ्यात्मक विवरण के साथ सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कथित रूप से कौन-से वोट प्रभावित हुए, किस बूथ या क्षेत्र में अनियमितता हुई और उसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा—इन सवालों के प्रमाण सामने रखे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार रक्फ़ की वैधता बरकरार रखी थी बिसेन ने 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय ने बिहार में किए गए रक्फ़ की वैधता बरकरार रखी थी। अदालत ने माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता के लिए रक्फ़करने का अधिकार है, साथ ही प्रक्रिया में आवश्यक कानूनी सुरक्षा उपाय भी लागू रहेंगे। हालांकि, रक्फ़को लेकर राजनीतिक विवाद समाप्त नहीं हुआ है। सितंबर 2026 में चुनाव आयोग के दो आयुक्तों द्वारा रक्फ़ से जुड़े कुछ निर्णयों पर आपत्ति दर्ज किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसलिए इस पूरे विवाद में आयोग के निर्णयों, आपत्तियों और राजनीतिक दलों के दावों को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया या मतदाता सूची में किसी गड़बड़ी पर आपत्ति है तो वह उपलब्ध संवैधानिक और न्यायिक माध्यमों के जरिए प्रमाण प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

सिवनी। सिवनी शहर के मंगलीपेठ और छिंदवाड़ा चौक में रविवार देर रात चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से धारदार चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

भीड़ के बीच चाकू लहरा रहा था आरोपी- कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने सोमवार दोपहर 12:20 बजे बताया कि रविवार रात करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल के सामने खेड़ापति मंदिर, मंगलीपेठ के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा थी और एक युवक धारदार चाकू हवा में लहराकर लोगों को भयभीत कर रहा था।

कमर में छिपाकर भागने की कोशिश की- पुलिस को मौके पर आता देखकर आरोपी ने चाकू कमर में छिपा लिया और वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान सिवनी निवासी प्रकाश मर्सकोले (46) के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसकी कमर से धारदार चाकू बरामद हुआ। चाकू रखने का वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया।

आर्म्स एक्ट में केस, पहले भी दर्ज हैं मामले

पुलिस ने प्रकाश मर्सकोले के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास सहित दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह रविवार रात करीब 2 बजे छिंदवाड़ा चौक में अंकित जैन नामक व्यक्ति को भी चाकू लेकर उत्पात करते पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से भी धारदार चाकू बरामद कर कार्रवाई की।

भोपाल में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग घेराव

बैरिकेड पर चढ़े, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन; कई कार्यकर्ता हुए घायल





भोपाल। एसआईआर के विरोध में भोपाल में निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने निकली कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प हुई। बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ताओं को रोकने पुलिस ने पानी की बौछार की। झड़प में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत कई घायल हो गए। प्रदर्शन में ज्ञानेश कुमार का मुखौटा लगाए कार्यकर्ता को जंजीरों में बांधकर प्रतीकात्मक विरोध भी किया गया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में सोमवार को भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और झंडे लहराने लगे। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर मौके से हटाया। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में उप नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे समेत कई घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला। उन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया।

ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर पहुंचे कार्यकर्ता : प्रदर्शन में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध भी किया। एक कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर पहुंचा। उसे जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया गया। जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन में शामिल नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए।

पीसीसी से शुरू हुआ प्रदर्शन : निर्वाचन आयोग कार्यालय के घेराव से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने सभा हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री और विधायक समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा के बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़े। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ताओं के बैरिकेड पार करने की कोशिश के बाद स्थिति बिगड़ी और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई।

एसआईआर को लेकर कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार विरोध कर रही है। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। कांग्रेस ने हटाए गए नामों का विधानसभा, जिला और कारणवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के बाद कई लोगों को बसों में बैठाकर मौके से हटाया।

स्टाप डेम के तरफ लाइफ जैकेट, रबर नाव जैसे सुरक्षा इंतजाम, दूसरी तरफ नदारद थी सुरक्षा

बैतूल। दो दिनों से प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। माचना नदी के उफनते स्टॉप डेम के एक तरफ नगर पालिका ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। दूसरी तरफ बिना किसी इंतजाम के लोग तेज बहाव के बीच विसर्जन करते रहे। दूसरी ओर न लाइट थी, न रबर बोट। न सुरक्षा गार्ड थे, न तैराक। स्थिति यह रही कि जिस जगह सुरक्षा इंतजाम थे, वहां से ज्यादा श्रद्धालु दूसरी तरफ पहुंच गए। ऊपर से पानी गिर रहा था। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। नीचे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी खतरा उठाकर पहुंचते रहे। लगातार तेज बारिश के कारण माचना एनीकट के दूसरी ओर बना 54 लाख लागत का स्टॉप डेम लबालब भर गया। इसकी सीढ़ियां पानी में डूब गईं। इसी जगह को विसर्जन स्थल बनाया गया था। होमगार्ड की मदद से एक तरफ रबर बोट पहुंचाई गई। इसमें हवा भरकर इसे 30 फीट से ज्यादा गहराई वाले पानी में तैनात किया गया। नगर पालिका अमले ने यहां चार कर्मचारियों को सिर्फ इसी काम के लिए लगाया। दूसरी तरफ रात में भी लोग बिना लाइट के आते रहे। खतरा मोल लेकर विसर्जन करते रहे। नगर पालिका सब इंजीनियर पंकज धुर्वे ने बताया कि होमगार्ड की ओर से रबर बोट तैनात की गई थी। दूसरी ओर भी सुरक्षा के प्रयास किए जाएंगे। जल निगम के आंकड़ों के अनुसार एनीकट में पानी का फ्लो औसतन 15 हजार लीटर प्रति सेकंड है। इससे माचना एनीकट के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। स्टॉप डेम लबालब होकर सीढ़ियों तक पहुंच गया। सेफ्टी रेलिंग तक डूब चुकी है। पहले भी यहां 20 साल के युवक की मौत हो चुकी है। शव तलाशने में 2 दिन लगे थे। इसी जगह दो बार अज्ञात लाशें भी मिल चुकी हैं। एनीकट के दूसरी ओर इस साल सबसे ज्यादा पानी है।



करंट वाले खंभे ने ली भाजपा युवा मोर्चा नेता की जान, पत्नी भी आई चपेट में



भोपाल। भोपाल के एमपी नगर में डीबी मॉल के सामने करंट की चपेट में आने से भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत हो गई। परिवार के साथ खरीदारी करने आए दिव्यऋषि सड़क पार करते समय स्ट्रीट लाइट के खंभे को पकड़ बैठे, उनकी पत्नी भी करंट की चपेट में आईं। राजधानी के एमपी नगर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत हो गई। वह परिवार के साथ डीबी मॉल में खरीदारी करने आए थे। लौटते समय सड़क पार करते हुए उन्होंने स्ट्रीट लाइट के खंभे को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि खंभे में करंट दौड़ रहा था। बिजली का झटका लगते ही वह मौके पर गिर पड़े। उनकी पत्नी भी करंट की चपेट में आईं, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को अलग कर लिया। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार परिवार ने अपना वाहन सड़क के दूसरी ओर खड़ा किया था। खरीदारी के बाद सभी लोग सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान दिव्यऋषि ने खंभे को सहारे के लिए पकड़ा और करंट की चपेट में आ गए। शुरूआती जानकारी में खंभे से एक तार निकला हुआ मिला है। पुलिस ने बाद में इस तार को अलग करवाया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जगदीश दांगी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने दिव्यऋषि को मौके पर उढफ देने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें नर्मदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अक्क्टर ले जाने की सलाह दी। पुलिसकर्मी उन्हें लेकर एआईआईएमएस पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बैतूल से लापता दो नाबालिग मुर्तिजापुर स्टेशन से मिलीं

बैतूल । सोनाघाटी चौकी क्षेत्र से बिना बताए घर से निकलीं दो नाबालिग बालिकाओं को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन से सकुशल दस्तयाब कर लिया। 26 सितंबर को दोनों के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 807/2026 और 808/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की। तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बालिकाओं की लोकेशन और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई। इसके बाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ से समन्वय कर आवश्यक जानकारी साझा की। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में कोतवाली टीआई देवकरण डेहरिया और सोनाघाटी चौकी प्रभारी चित्रा कुमरे के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। मुर्तिजापुर स्टेशन से दोनों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि 26 सितंबर को दोनों के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी गई थी।

फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह केस में शिकायतकर्ता रोहित भी आरोपी

नौकरी लगवाने झांसा देने का आरोप, एफआईआर दर्ज



भोपाल। फर्जी आईएएस बनकर ठगी के आरोपों में घिरी तृप्ति सिंह के मामले में पुलिस जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। जिस रोहित लिल्हारे ने तृप्ति के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी, अब बागसेवनिया पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक रोहित ने तृप्ति के कहने पर एक युवती से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत में युवती को नौकरी लगने और जॉइनिंग से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भरोसा दिलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार रोहित ने युवती से कहा था कि जॉइनिंग और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और सिर्फ मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) से सत्यापन बाकी है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल की जांच के बाद रोहित की भूमिका को संदिग्ध माना और उसे मामले में आरोपी बनाया। पुलिस ने रोहित के बयान दर्ज किए। अब जांच में उसके तृप्ति के साथ संपर्क, संबंधित युवती से हुई बातचीत और बैंक खातों में हुए लेन-देन को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि तृप्ति और रोहित के बीच किस तरह की बातचीत होती थी और नौकरी से जुड़े दावों में उसकी भूमिका क्या थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि तृप्ति ने विधानसभा परिसर में युवतियों के साथ बनाए गए कुछ वीडियो रोहित को भेजे थे। इन वीडियो के जरिए नौकरी लगवाने की बात कहे जाने की जानकारी भी पुलिस के सामने आई है।

रायसेन में 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़क खराब

वोटिंग बहिष्कार का ऐलान; उपचुनाव से एक दिन पहले ग्रामीण बोले- रोड नहीं तो वोट नहीं



रायसेन। रायसेन में जिला पंचायत वार्ड-3 के उपचुनाव से एक दिन पहले सालेरा और मऊ पथराई गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। खराब सड़क से नाराज ग्रामीणों ने 'रोड नहीं तो वोट नहीं' के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि रायसेन से सालेरा तक करीब 8 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री सड़क खराब है। यह मऊपटराई और सालेरा पंचायतों को जोड़ती है, जिससे 40 से ज्यादा गांवों के लोगों का आना-जाना होता है।

मंजूरी हुई लेकिन काम नहीं हुआ : पूर्व सरपंच झलकन बैरागी ने बताया कि 2023 में सूंड-सालेरा मार्ग की मरम्मत मंजूर हुई थी, पर काम नहीं हुआ। सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक से मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए गए, पर हल नहीं निकला। सड़क की खराब हालत से तीन लोगों की जान जा चुकी है। इनमें विदिशा के दो युवक भी थे, जिनकी बाइक गड्ढे में आने के बाद बिजली के पोल से टकरा गई थी। जिला पंचायत वार्ड-3 में 29 सितंबर को मतदान होना है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक सड़क की मरम्मत शुरू नहीं होती, वे वोट नहीं डालेंगे।

न्यूनतम वेतन के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे कर्मचारी

3 से 5 हजार रुपए पाने वाले अस्थायी श्रमिकों का धरना; उमा भारती की 2003 की घोषणा याद दिला रहे



भोपाल। भोपाल में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर 3 से 8 हजार रुपए वेतन पाने वाले अस्थायी, अंशकालीन, चौकीदार और ठेका श्रमिक सोमवार सुबह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को खदेड़ा तो बोर्ड आफिस की ओर रैली निकालकर नारेबाजी करते पहुंचे। ह्यून्यूनतम वेतन दिलाओ उपवास आंदोलनह्ल के तहत वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को वर्ष 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की ओर से की गई घोषणा की याद दिला रहे हैं।

घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान का दावा : अस्थायी, आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम मजदूरी 12,425 से 16,769 रुपए प्रति माह है। उनका दावा है कि सरकार अपने विभागों में कर्मचारियों से 3 से 5 हजार रुपए में काम करा रही है। शर्मा के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में भी ठेका श्रमिकों को पूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। इससे अस्थायी और ठेका श्रमिक कर्मचारियों में असंतोष है। आंदोलन की पूर्व सूचना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल को पत्र के जरिए दी गई थी।

11 वर्ग के कर्मचारी आंदोलन में शामिल : वासुदेव शर्मा के अनुसार, आंदोलन करने वाले कर्मचारियों ने इसका नाम ह्यून्यूनतम वेतन दिलाओ उपवास आंदोलनह्ल रखा है। इसमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, सफाईकर्मी और लोकल यूथ सर्वेयर बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इनमें कुछ कर्मचारियों को 2 से 3 हजार रुपए ही मिलते हैं। शर्मा के अनुसार, शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों व छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। इनसे सरकार 4 से 5 हजार रुपए में 10 से 12 घंटे काम करा रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र : वासुदेव शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश की मेहनतकश जनता वर्ष 2003 से लगातार भाजपा सरकार को चुनती आ रही है। पत्र में दावा किया गया है कि बीते 23 साल में चपरासी तक की स्थायी नौकरी नहीं दी गई है। पत्र के मुताबिक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियां पूरी तरह खत्म कर उन्हें अस्थायी और आउटसोर्स कर दिया गया है। ये नौकरियां गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए थीं। पत्र में कहा गया है कि इन नौकरियों में न तो रोजगार का स्थायित्व है और न ही सम्मानजनक वेतन। वर्ष 2003 से पहले मिलने वाली नौकरियों में सेवा सुरक्षा हुआ करती थी।

रायसेन में पटवारी बोले- निष्पादन से नाम हटाएं

संशोधन के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम फिर ज्ञापन दिया



रायसेन। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने सोमवार को रायसेन में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम मनोज उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन-2026 में पटवारियों को निष्पादक की जिम्मेदारी से अलग करने की मांग की। संघ ने शासन की ओर से किए गए संशोधन को भी अपर्याप्त बताया। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि संशोधन के बाद भी पटवारियों को इस जिम्मेदारी से अलग नहीं किया गया है। नाम, पहचान या अभिलेख से जुड़ी गड़बड़ी होने पर पटवारी की व्यक्तिगत जवाबदेही बन सकती है। संघ का कहना है कि गांव में हर व्यक्ति की पहचान और निवास की पुष्टि करना पटवारी के लिए संभव नहीं है। सरपंच और सचिव का ग्रामीणों से सीधा संपर्क रहता है, इसलिए हितग्राही का सत्यापन पंचायत स्तर पर कराने की मांग की गई है। संघ ने मुख्यमंत्री से पटवारियों को निष्पादन की जिम्मेदारी से अलग कर अंतिम फैसला सक्षम अधिकारी के स्तर पर कराने की मांग की है।

छिंदवाड़ा में एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक गिरफ्तार



छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सागरपेशा प्राथमिक शाला के ग्राउंड से दो युवकों को टऊ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से 8.05 ग्राम एमडी ड्रग्स, दो मोबाइल फोन और 700 रुपए नकद बरामद हुए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 2 लाख 24 हजार 700 रुपए बताई गई है। पुलिस को 26 सितंबर को सूचना मिली थी कि फैजान खान (27), निवासी पुराना बैल बाजार और जैद फराज (25), निवासी हुसैन नगर, सागरपेशा प्राथमिक शाला के ग्राउंड में एमडी ड्रग्स बेचने के लिए मौजूद हैं। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने बताए गए हुलिए के आधार पर दोनों युवकों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में 8.05 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर, दो मोबाइल फोन और 700 रुपए मिले। पुलिस ने सभी सामग्री जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने एमडी ड्रग्स नागपुर के बाबू उर्फ मारुक खान से खरीदने की बात बताई है। पुलिस अब ड्रग्स की खरीद-बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

समय-सीमा बैठक में की विभागीय योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा

कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों के प्रति जताई नाराजगी



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कहा कि सभी अधिकारी बैठक में तैयारी और अद्यतन जानकारी के साथ आयें और शिकायतों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत कम पंजीयन पर नाराजगी जाहिर करते हुये महिला एवं बाल विकासखंड परियोजना विजयराघवगढ़ के परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बैठक में समय-सीमा के लंबित पत्रों की जानकारी के बिना आने पर मार्कफेड के अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुये उन्होंने इस संबंध में मार्कफेड के प्रबंध संचालक (एमडी) को पत्र लिखकर अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने पटवारियों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी एसएलआर को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़क मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश

कलेक्टर ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम अब समाप्त हो गया है, इसलिये सभी विभाग सड़क मरम्मत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं, ताकि आवागमन में नागरिकों को परेशानी न हो।

ठेकेदारों और हितग्राहियों का करें शीघ्र भुगतान

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ठेकेदारों के भुगतान सहित चाय-नाश्ता, फोटोकॉपी सहित विभिन्न मदों के भुगतान तथा हितग्राहियों के देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण हेतु मिली सराहना

कलेक्टर श्री तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में कटनी जिले को प्रदेश में द्वितीय स्थान मिलने पर सराहना करते हुये सभी विभागों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 2 अक्टूबर को पहाड़ी में आयोजित होने वाले आगामी शिविर हेतु चयनित सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में लायें अपेक्षित प्रगति

कलेक्टर श्री तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माताओं की एएनसी जांच एवं एनीमिया के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए परियोजना ढीमरखेड़ा एवं कटनी शहरी में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, जन्म प्रमाण पत्र, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पंजीयन, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की स्थिति तथा पोषण ट्रैकर में चिन्हांकित सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की भी समीक्षा की।

न्यायालयों व आयोगों से जुड़े मामलों में दें प्रतिवेदन

कलेक्टर श्री तिवारी ने नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित जिला अधिकारियों को अपने विभागों से जुड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और मानवाधिकार आयोग तथा बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त एवं सीएम हेल्पलाइन, मॉनिट और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के मामलों में समय पर प्रतिवेदन और जवाब दावा करने के निर्देश दिए।

पीएम किसान ई-केवाईसी का कार्य एक सप्ताह में पूरा करें

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, डिजिटाइजेशन एवं पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने 30 सितंबर तक खरीफ गिरदावरी का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित एवं स्वीकृत प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी कराने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विशेष रूप से नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में समस्त एसडीएम, उपसंचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष नायक, जिला पंजीयक पंकज कोरी, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती पर युवाओं ने निकाली भव्य बाइक रैली

इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजा पवई



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती पर सोमवार को पवई नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया युवाओं की बाइक रैली से नगर की गलियांह्लइंकलाब जिंदाबादह्वऔरह्लशहीद भगत सिंह अमर रहेंह्व के नारों से गूंज उठीं हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए युवाओं का काफिला जब नगर के प्रमुख मार्गों से निकला तो जगह-जगह नगरवासियों ने फूलों की वर्षा कर रैली का आत्मीय स्वागत किया बाइक रैली का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर से हुआ युवाओं का काफिला नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचा, जहां रैली का समापन किया गया पूरे मार्ग में युवाओं ने भगत सिंह के विचारों और उनके राष्ट्रप्रेम से जुड़े नारे लगाए। रैली ने नगर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया।

,,देश की आजादी के लिए युवावस्था में समर्पित कर दिया जीवन,,- सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था बचपन से ही उनके मन में देश को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से मुक्त कराने का जुनून था जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला उन्होंने युवावस्था में ही क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता अपनाया और युवाओं को संगठित कर देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उनकी मृत्यु ने भगत सिंह को झकझोर दिया इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्रवाई की वहीं 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई और गिरफ्तारी दी इसके बाद उन्होंने जेल में भी अपने विचारों और संघर्ष के माध्यम से देशवासियों को जागरूक किया 23 वर्ष की उम्र में हंसते-हंसते चढ़ गए फांसी के फंदे पर लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह,राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई 23 मार्च 1931 को तीनों अमर शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए महज 23 वर्ष की आयु में दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान आज भी देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

आज भी युवाओं के दिलों में जिंदा है भगत सिंह का विचार- रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि भगत सिंह केवल एक नाम नहीं,बल्कि साहस,त्याग,संघर्ष और राष्ट्रप्रेम की अमर पहचान हैं उन्होंने अपने छोटे से जीवन में देश की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है उनके विचार आज भी युवाओं को देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं भगत सिंह की जयंती पर निकली बाइक रैली के दौरान ,इंकलाब जिंदाबाद,शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहें, जैसे नारों से पूरा पवई नगर गूंजता रहा रैली ने न केवल शहीद भगत सिंह के बलिदान को नमन किया, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी मजबूती से अभिव्यक्त किया।

अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा पैदल मार्च,

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीस खान ने किया आह्वान

30 सितंबर को कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन



पन्ना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निदेर्शानुसार कांग्रेस द्वारा 30 सितंबर, बुधवार को पन्ना जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसजन जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:30 बजे अंबेडकर चौक पर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। यहां से जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीस खान ने जिलेभर के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। मतदाता सूची में हुए बदलावों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विषयों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा आवश्यक है। अनीस खान ने प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों, मोर्चा-संगठनों, विभाग एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर अंबेडकर चौक पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।



पन्ना जिला अस्पताल में मरीजों को फल, प्रसूता महिलाओं को मैटरनिटी एवं नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरित

दिवंगत यदुपति सिंहानिया जी की जयंती पर जेके सीमेंट की सेवा पहल

दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। दिवंगत श्री यदुपति सिंहानिया जी की जयंती के अवसर पर जेके सीमेंट परिवार द्वारा सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए पन्ना जिला अस्पताल में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को ताजे फलों का वितरण किया गया। वहीं प्रसूता महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित मैटरनिटी किट तथा नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट वितरित की गई। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. राजेश तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. आलोक गुप्ता एवं पूर्व सीएमएचओ डॉ. एस.के. त्रिपाठी सहित अस्पताल के चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जेके सीमेंट की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों, प्रसूता महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए इस प्रकार का सहयोग उपयोगी एवं सराहनीय है। जेके सीमेंट प्लांट प्रबंधन की ओर से यूनिट हेड श्री कपिल अग्रवाल एवं एचआर हेड श्री अवनेश गौतम सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। प्रबंधन ने कहा कि दिवंगत श्री यदुपति सिंहानिया जी का जीवन सामाजिक सरोकार और जनसेवा की भावना से प्रेरित रहा। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जेके सीमेंट द्वारा उरफके माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों ने फल और किट वितरण के लिए जेके सीमेंट परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिवंगत श्री यदुपति सिंहानिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को याद किया।

ग्राम पंचायत कमता में श्री राम हॉस्पिटल का स्वास्थ्य शिविर आयोजित



पवई। श्री राम हॉस्पिटल की संचालक श्रीमती आरती विश्वकर्मा की पहल पर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार, 28 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत कमता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर अंतिम बागरी (एमबीबीएस), स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. महादेव शर्मा,सीनियर नर्स स्टाफ प्रेमलता विश्वकर्मा,लेव टेक्नीशियन रोशनी बानो एवं फार्मासिस्ट बृजेश कुमार विश्वकर्मा ,एम्बुलेंस चालक बलराम पटेल सहित स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, शुगर, बीपी सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर आवश्यक उपचार ,दवा वितरण एवं परामर्श दिया गया। इस दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया

NIIRD हैदराबाद से आए राज्य स्तरीय कंसल्टेंट श्री आठिया ने घंघरी कला एवं चाका ग्राम पंचायत का किया भ्रमण

OSR में नवाचार और बेहतर प्रयासों को मिला राष्ट्र स्तरीय पहचान का मंच



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन में पंचायतों में OSR (Own Source Revenue) बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों, नवाचारों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का जायजा लेने के लिए भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान ठक्कमक्क हैदराबाद से आए राष्ट्र स्तरीय कंसल्टेंट श्री अमित आठिया द्वारा जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत घंघरी कला एवं ग्राम पंचायत चाका का स्थल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कंसल्टेंट श्री अमित आठिया ने दोनों ग्राम पंचायतों में डरफ से संबंधित गतिविधियों की भौतिक स्थिति का अवलोकन किया तथा पंचायत स्तर पर राजस्व के स्वयं के स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पंचायतों द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों, कार्यप्रणाली एवं स्थानीय स्तर पर राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयोगों को समझा तथा अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर आ रही कठिनाइयों की भी जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा धरातल पर डरफ को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयोगों एवं प्रयासों से राज्य स्तरीय कंसल्टेंट को अवगत कराया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा सीमित संसाधनों के बीच किए जा रहे नवाचारों और बेहतर प्रबंधन को देखकर श्री अमित आठिया ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा इन प्रयासों को सराहनीय बताया।

राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तक पहुंचा कटनी के प्रयासों का उल्लेख

OSR के क्षेत्र में कटनी जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नवाचारों की जानकारी ठक्कमक्क हैदराबाद जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंचना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे जिले में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्त्रोत विकसित करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नई पहचान मिली है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डरफबढ़ाने के साथ-साथ नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। घंघरी कला एवं चाका ग्राम पंचायत का यह भ्रमण इन्हीं प्रयासों की धरातलीय समीक्षा एवं अनुभवों के आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण कड़ी रहा। इस दौरान आरजीसीए के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री पंकज नामदेव, ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

दीपावली पर पटाखा विक्रय के लिए ऑनलाइन जारी होंगे अस्थाई लाइसेंस

कटनी । आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के फुटकर विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उनकी विधिवत जांच एवं संबंधित अधिकारियों के अभिमत के आधार पर अस्थाई लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अस्थाई अनुज्ञप्ति की अवधि धनतेरस से ग्यारस तक 15 दिवस निर्धारित की गई है। इस संबंध में अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा ने आयुक्त, नगर निगम सहित सभी एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है।

एमपी सर्विसेज पोर्टल से होंगे आवेदन

अस्थाई आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन प्रारूप ए.ई.-5 में 500 रुपये के बैंक चालान (मद 0070-60103) के साथ आवेदन करना होगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी आवेदनों की जांच कर प्रतिवेदन एवं अभिमत प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन अनुज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही करेंगे। आवेदन प्रक्रिया के लिए MP Services PortÔl के माध्यम से अनुभागवार यूजर आईडी उपलब्ध कराई गई हैं। जारी अनुज्ञप्तियों की प्रतियां जिला कार्यालय को भी भेजी जाएंगी।

एलएसडीए मॉड्यूल से ऑनलाइन जारी होंगे अनुज्ञापत्र- पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के निदेर्शों के अनुसार विस्फोटक नियमों के तहत जारी होने वाली एनओसी एवं विस्फोटक परिसरों से संबंधित अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन माध्यम से एलएसडीए मॉड्यूल के जरिए जारी की जाएंगी। इनमें दीपावली पर्व पर अस्थाई पटाखा विक्रय के अनुज्ञापत्र भी शामिल हैं।

आबादी से दूर सुरक्षित स्थानों पर लगेंगे पटाखा बाजार- सुरक्षा एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के फुटकर विक्रय के लिए आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थलों का संयुक्त रूप से चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित स्थलों पर शर्तों के साथ पटाखा विक्रय बाजार लगाने की अनुमति दी जाएगी। इन स्थलों का लेआउट निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप तैयार कराया जाएगा। निदेर्शों के तहत जारी अस्थाई अनुज्ञप्तियों तथा तैयार किए गए लेआउट की एक-एक प्रति उपसंचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग तथा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

ओम होम हैल्थ केयर सर्विस
हमारे पास अशक्त बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु नर्स,वार्ड वॉय,आया बाई,फिजियोथैरेपी और दवाईयाँ घर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रो.जितेन्द्र पटैल CERVIC - 24X7 Hourse
मो. 9340721556,9753518166
पता-केनरा बैंक महाराष्ट्र हॉई स्कूल गोल बाजार जबलपुर(म.प्र.)

Manufacturer of t-shirts & lowers Mo. 9174614421, 9406763810
CHANDRAKALA TEXTILES
सभी प्रकार की टी-शर्ट ऑर्डर पर बनाई और प्रिंट की जाती हैं और स्पोर्ट्स सबलिमेसन जर्सी बनाई जाती हैं।
Address : shop no 151, jabalpur fashion design cluster market Lema garden Gohalpur jabalpur 482001

चाबी पंचायत ने बनाया "हवा में तालाब" करीब साढ़े चार लाख के कार्य पर सवाल.? सरपंच के भाई को लाभ पहुंचाने के आरोप; मस्टर रोल से लेकर जियो टैगिंग तक जांच की मांग

कागजों में बना खेत तालाब, जमीन पर नहीं मिला निर्माण!

दैनिक रेवांचल टाइम्स मोहगांव/मंडला। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा खेत तालाब सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन जनपद पंचायत मोहगांव की ग्राम पंचायत चाबी में खेत तालाब निर्माण से जुड़ा एक मामला इन योजनाओं की निगरानी और कार्यों के भौतिक सत्यापन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहगांव जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चाबी के बगली मोहल्ले में एक हितग्राही के नाम पर खेत तालाब निर्माण के लिए करीब चार से साढ़े चार लाख रुपये की राशि स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि जिस स्थान पर तालाब निर्माण दशार्या गया है, मौके पर वहां तालाब का अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज निर्माण और जमीन की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को लेकर जांच की मांग उठ रही है।

सरपंच के भाई को लाभ देने का आरोप

स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उक्त योजना का लाभ पंचायत के सरपंच के भाई को दिया गया। संबंधित हितग्राही के रूप में सेवकराम धुर्वे पिता देवी सिंह धुर्वे का नाम सामने आ रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 85/2, जिसका कुल रकबा करीब 0.29 हेक्टेयर बताया जा रहा है, सेवकराम धुर्वे के नाम दर्ज है। यदि इसी भूमि पर खेत तालाब निर्माण स्वीकृत और पूर्ण दशार्या गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौके पर वह तालाब कहां है?

कागजों में तालाब, जमीन पर गायब!

खेत तालाब योजना का उद्देश्य किसान के खेत में जल संरक्षण की संरचना तैयार कर वर्षा जल को रोकना तथा सिंचाई के लिए उसका उपयोग करना है। ऐसे में यदि स्वीकृत स्थल पर वास्तविक निर्माण नहीं हुआ है, तो कई प्रक्रियागत सवाल सामने आते हैं। मसलन– कार्य की माप किस आधार पर की गई? कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र कैसे जारी हुआ?*मस्टर रोल में मजदूरों की उपस्थिति कैसे दर्ज हुई? मजदूरी का भुगतान किन लोगों को किया गया? कार्य की जियो टैगिंग और फोटो किस स्थान की है? इन सभी सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों और मौके के भौतिक सत्यापन के बाद ही सामने आ सकता है।

चार लाख से अधिक की राशि, फिर तालाब कहां?

बताया जा रहा है कि खेत तालाब निर्माण की लागत करीब चार से साढ़े चार लाख रुपये के आसपास है। इतनी बड़ी राशि से स्वीकृत कार्य यदि वास्तव में पूर्ण हुआ है तो उसका स्पष्ट भौतिक स्वरूप मौके पर दिखाई देना चाहिए। मनरेगा अथवा संबंधित योजना के कार्यों में मजदूरी भुगतान, प्रशासन को स्वीकृति आदेश, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, जियो टैगिंग और कार्यस्थल की फोटों का मिलान और मौके की वास्तविक स्थिति से करना होगा। जब मौके पर तलाब ही नहीं हैं तो इन सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच अतिआवश्यक हो जाती हैं।

मजदूरों के भुगतान की भी हो पड़ताल

यदि जांच में तालाब निर्माण मौके पर नहीं पाया जाता है तो केवल निर्माण कार्य की जांच पर्याप्त नहीं होगी। मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों से भी पूछताछ की आवश्यकता होगी कि उन्होंने किस स्थान पर काम किया, कितने दिन काम किया और उन्हें कितनी मजदूरी प्राप्त हुई।साथ ही मजदूरी भुगतान की तारीख और संबंधित बैंक खातों की जानकारी का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जाना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही जांच के बाद में यदि रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अन्तर मिलता है तो यह केवल लापरवाही का मामला नहीं बनता बल्कि जानबूझ कर सरकारी धन को अमानत में खयानत पहुंचाने जैसा गंभीर अपराध साबित होता हैं।

रोजगार सहायक से लेकर तकनीकी अमले तक की भूमिका जांच के दायरे में

पंचायत एवं मनरेगा से जुड़े कार्यों को लेकर पंचायत कार्यों में रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, उपयंत्री, और अन्य अधिकारियों की स्वीकृति के साथ ही स्थल सत्यापन, माप, मस्टर रोल और भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों से गुजरती है। ऐसे में यदि जांच में सरकारी रिकॉर्ड में तालाब पूर्ण पाया जाता है, लेकिन जमीन पर उसका अस्तित्व नहीं मिलता, तो केवल पंचायत पदाधिकारियों की भूमिका ही नहीं बल्कि कार्य से जुड़े जिम्मेदार कर्मचारियों और तकनीकी अमले की भूमिका की भी जांच आवश्यक होगी। सवाल यह भी है कि यदि कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था तो मौके पर निर्माण की वास्तविक स्थिति सामने क्यों नहीं आई? और यदि भौतिक सत्यापन



नहीं हुआ तो भुगतान किस आधार पर किया गया?

हवा में तालाब ने खोली निगरानी व्यवस्था की पोल

सरकार जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। खेत तालाब जैसी योजनाओं का सीधा उद्देश्य किसानों को पानी उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को मजबूती देना है। ऐसे में यदि कोई कार्य केवल दस्तावेजों में पूर्ण दिखाया गया हो और जमीन पर उसका अस्तित्व न मिले, तो योजना के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े होते हैं। चाबी पंचायत का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कथित तौर पर हितग्राही की जमीन, खसरा नंबर और सरकारी भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध होने की बात सामने आ रही है। अब आवश्यकता है कि रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का निष्पक्ष मिलान कराया जाए।

जांच हुई तो सामने आ सकते हैं कई तथ्य

सूत्रों से प्राप्त जानकारीनुसार यदि मामले की निष्पक्ष जांच में खसरा नंबर 85/2 का स्थल निरीक्षण, राजस्व नक्शे से मिलान, तालाब की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, कार्यस्थल की तस्वीरें और जियो टैगिंग की जांच महत्वपूर्ण होगी।इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित हितग्राही योजना की पात्रता पूरी करता था या नहीं तथा पंचायत पदाधिकारियों से उसके संबंध का योजना के लाभ से कोई प्रत्यक्ष संबंध था या नहीं।

अधिकारी बोले–लिखित शिकायत मिलने पर होगी जांच

मामले को लेकर जनपद पंचायत मोहगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल रंधावा ने कहा कि ह्लआप लिखित में शिकायत कीजिए, टीम भेजकर जांच करा ली जाएगी।ह्व अब देखना यह होगा कि शिकायत के बाद जांच टीम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करती है या मामला केवल कागजी जांच तक सीमित रह जाता है।

अब सवाल–आखिर तालाब बना कहां?

चाबी पंचायत का कथित खेत तालाब मामला ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। यदि रिकॉर्ड में तालाब पूर्ण है और मौके पर उसका अस्तित्व नहीं मिलता, तो यह अंतर कैसे पैदा हुआ–इसका जवाब जांच से ही सामने आएगा। सरकारी रिकॉर्ड में तालाब, सरकारी खजाने से भुगतान और जमीन पर निर्माण नहीं–अब जांच ही बताएगी कि चाबी पंचायत में आखिर वह खेत तालाब बना कहां था? यह तो निकट भविष्य में आने वाले समय पर ही तय होगा कि खबर प्रकाशन और शिकायत के बाद जांच टीम मौके पर कब तक पहुंच पाती हैं.! और यदि मौके पर पहुंच भी जाती हैं तो जांच कितनी निष्पक्षता पूर्वक की जाती हैं। या केवल जांच के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता हैं। फिलहाल चाबी का यह कथित "*हवा में बना तालाब*" ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया हैं..एक तरफ भारत सरकार के साथ ही आमजनता कहती हैं पानी बचाइए भविष्य सँवारिए.! तो वहीं चाबी पंचायत के जिम्मेदार जब जमीन में ही तालाब नहीं बनाएंगे तो फिर पानी बचेगा कैसे और आमजनता के साथ ही किसान का भविष्य संवरेगा कैसे.?

क्या कहते हैं जिम्मेदार..

ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं हैं आपके माध्यम से मुझे पता चला है यदि ऐसा कुछ गलत हुआ हैं तो शिकायत के बाद निश्चित ही जांच की जायेगी और कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।

कमल रंधावा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मोहगांव

मैं ग्राम पंचायत में नया नया आया हूं मेरी जानकारी में नही है कल बता पाऊंगा।

ढोकल मरकाम, सचिव ग्राम पंचायत चाबी मोहगाँव

चौराहा नामकरण की मांग जयंती पर माल्यार्पण



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मण्डला। बुधवारी चौंक स्थित अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील दुबे अन्ना महाराज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सोनी, भारतीय सेवा परिषद अध्यक्ष अजय वंशकार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री दुबे ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश के अमर शहीदों की अनेक प्रतिमा नगर में स्थापित कराई गई है। ये प्रतिमाएं नागपुर में तैयार की गई थी इनकी सुरक्षा और संरक्षण पर नगर पालिका लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बुधवारी चौंक का नाम शहीद भगत सिंह चौक होना चाहिए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज इस महत्वपूर्ण दिन में यहां पर साफ सफाई न होना नगर पालिका की लापरवाही को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि इन शहीदों के स्मारकों के सौन्दर्यीकरण में भी लापरवाही बरती जा रही है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी को नमन करते हुए उनके आदर्शों को स्मरण किया कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवियों ने कहा कि शहीद भगत सिंह जैसे राष्ट्रभक्तों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रहित को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनका जीवन त्याग कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण संकल्प और उच्च लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था का प्रेरणादायी उदाहरण है। ऐसे महापुरुषों का जीवन आने वाली पीढ़ि?ों को भी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता रहेगा। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके पद या संपत्ति से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। समय बीतने के साथ बहुत सी चीजें धुंधली पड़ जाती हैं लेकिन महान व्यक्तित्वों के आदर्श और उनके चरित्र की छाप समाज में लंबे समय तक बनी रहती है ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न

दैनिक रेवाँचल टाईम्स - नैनपुर, म.प्र.जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत समाज कार्य स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन केन्द्र शासकीय स्नातक महाविद्यालय नैनपुर में जिला समन्वयक श्री सुशील बर्मन जी के निर्देशन और ब्लॉक समन्वयक श्रीमति सीता उइके जी के मार्गदर्शन में छात्र -छात्राओं, परामर्शदाताओं की सहभागिता से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर के उपलक्ष्य में 27 सितंबर रविवार को संचालित समाज कार्य स्नातक स्नातकोत्तर सम्पर्क कक्षा के दौरान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यातिथि श्री अविनाश नामदेव नगर विकास समिति नैनपुर,श्री सुधीर बंदेवार पिछड़ा वर्ग मोर्चा मीडिया प्रभारी नैनपुर, श्री प्रवीण छोटे ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडला विभाग संयोजक, श्री जयदीप गोविंद भारतिया सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जनपद पंचायत नैनपुर और मुख्य वक्ता सुश्री अक्षिता नामदेव,श्री अखिलेश शुक्ला जी समाज सेवी नैनपुर द्वारा मां सरस्वती के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रवक्ता सुश्री अक्षिता नामदेव द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन गाथा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। प्रवक्ता श्री प्रवीण छोटे ठाकुर द्वारा उनके संघर्षमय जीवन की गाथा पर प्रकाश डाला गया। प्रवक्ता श्री पंडित अखिलेश शुक्ला जी द्वारा वर्तमान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं विशेष कर दीनदयाल अंत्योदय योजना पर विस्तृत जानकारी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुख्य रूप से एकात्म मानववाद के दर्शन और अंत्योदय के विचार के लिए प्रसिद्ध हैं।वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान चिंतक थे। दीनदयाल जी ने ही अंत्योदय का नारा दिया जिसका अर्थ है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति का विकास हो। उनके अनुसार राष्ट्र की असली प्रगति तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय चिन्तकों के आदर्श और मार्गदर्शनों हमें आत्मसात कर राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देने सदैव तत्पर रहना चाहिए तभी बसका साथ सबका विकास संभव है। अंत में विकासखण्ड समन्वयक श्रीमति सीता उइके जी द्वारा उपस्थिति प्रबुद्धजन वक्ताओं का आभार व्यक्त कर संगोष्ठी कार्यक्रम का समापन किया गया।

तहसील मुख्यालय से करीब 300 मीटर दूर चल रहा शासकीय निर्माण न योजना की जानकारी, न लागत का खुलासा–पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी को लेकर सवाल

दैनिक रेवांचल टाईम्स - घुघरी। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के तहसील मुख्यालय घुघरी की ग्राम पंचायत पांडकला में बन रहे शासकीय आवास/विश्राम गृह को लेकर निर्माण से ज्यादा अब उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) से करीब 300 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन मौके पर ऐसा कोई स्पष्ट सूचना पट्ट दिखाई नहीं दे रहा, जिससे आम नागरिक यह जान सके कि भवन किस योजना अथवा मद से बनाया जा रहा है, इसकी स्वीकृत लागत कितनी है और निर्माण की जिम्मेदारी किस विभाग अथवा एजेंसी के पास है। निर्माण शासकीय धनराशि से कराया जा रहा बताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासनिक स्वीकृति, लागत, कार्यादेश, निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की अवधि और तकनीकी निगरानी जैसी बुनियादी जानकारियों को स्पष्ट किया जाना सार्वजनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

सूचना पट्ट आखिर क्यों नहीं? सरकारी निर्माण में सूचना सार्वजनिक करने का उद्देश्य यह है कि नागरिक यह जान सकें कि सार्वजनिक धन से कौन-सा कार्य कराया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। निर्माण संबंधी अभिलेखों में कार्य की स्वीकृति, अनुमान, अनुबंध, एजेंसी, कार्य अवधि और भुगतान जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। ऐसे में पांडकला के निर्माण स्थल पर यदि सूचना पट्ट प्रदर्शित नहीं है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि निर्माण से संबंधित जानकारी आम नागरिकों के लिए किस माध्यम से उपलब्ध कराई गई है?

सवाल पारदर्शिता का है, अवैध निर्माण घोषित करने का नहीं

केवल सूचना बोर्ड दिखाई न देने के आधार पर दैनिक रेवांचल टाईम्स यह निष्कर्ष नहीं निकाल रहा कि निर्माण अवैध है अथवा सरकारी धन में अनियमितता हुई है। संबंधित विभाग से निर्माण की स्वीकृति, लागत, कार्यादेश और तकनीकी निगरानी से जुड़े तथ्य सार्वजनिक करने की अपेक्षा है।

आखिर किस मद से बन रहा है भवन? निर्माण स्थल को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भवन की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से जुड़े हैं। यदि संबंधित विभाग इनका विवरण सार्वजनिक करता है तो निर्माण को लेकर उत्पन्न संशय भी दूर हो सकता है।

बोर्ड गायब, जानकारी गायब और निर्माण जारी! घुघरी में बन रहे विश्राम गृह पर उठे सवाल



इन सवालों के जवाब जरूरी

01. प्रशासनिक स्वीकृति किस विभाग अथवा प्राधिकारी ने जारी की? 02. कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई?
03. राशि किस योजना अथवा मद से जारी हुई?
04. तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी ने दी?
05. निविदा किस प्रक्रिया से हुई?
06. कार्यादेश किस एजेंसी अथवा ठेकेदार को दिया गया?
07. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?
निर्माण के तकनीकी मापदंड क्या हैं?
सरकारी निर्माण में स्वीकृत अनुमान, ड्रॉइंग और तकनीकी २स्त्रीू३ङ्मल्ल२ महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कार्य स्वीकृत तकनीकी मापदंड और लागू दर अनुसूची के अनुरूप कराया जा रहा है या नहीं। सीमेंट की निर्धारित गुणवत्ता सरिया का ग्रेड और आकार कंक्रीट का निर्धारित अनुपात ईंट/ब्लॉक की गुणवत्ता नींव की निर्धारित गहराई दीवार और प्लास्टर की मोटाई फर्श में उपयोग होने वाली सामग्री बिजली एवं पानी फिटिंग के मानक इन मापदंडों का वास्तविक निर्धारण स्वीकृत अनुमान, ड्रॉइंग, तकनीकी २स्त्रीू-३ङ्मल्ल२ और संबंधित विभाग के दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकता है। इसलिए इन्हें सार्वजनिक किए जाने से निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों का तथ्यात्मक जवाब सामने आ सकता है।

गुणवत्ता पर सवाल उठे तो जिम्मेदार कौन? अभी भवन की नींव और प्रारंभिक संरचना का निर्माण दिखाई दे रहा है। ऐसे में निर्माण पूरा होने से पहले तकनीकी निगरानी से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मौके पर नियमित तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो रही है? क्या निर्माण स्वीकृत ड्रॉइंग और अनुमान के अनुरूप है?

क्या माप पुस्तिका में वास्तविक कार्य की मात्रा दर्ज की जा रही है? क्या भुगतान सत्यापित कार्य के आधार पर किया जाएगा? नियमों की अनदेखी या सिर्फ सूचना की कमी? मौके पर सूचना पट्ट दिखाई नहीं देने और निर्माण की स्वीकृति, लागत तथा एजेंसी से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होने से पारदर्शिता पर सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि इसका उत्तर संबंधित विभाग के आधिकारिक अभिलेख सामने आने के बाद ही तथ्यात्मक रूप से मिल सकता है। सार्वजनिक धन से होने वाले निर्माण में स्वीकृति, भुगतान, माप और वास्तविक कार्य से जुड़े रिकॉर्ड जांच एवं ऑडिट के दायरे में आते हैं। ऐसे में संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से निर्माण को लेकर उत्पन्न संदेह और सवाल दोनों दूर किए जा सकते हैं।

प्रशासन से जनता के 12 सीधे सवाल
1. विश्राम गृह/शासकीय आवास के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति किसने दी?
2. इसकी कुल स्वीकृत लागत कितनी है?
3. राशि किस योजना अथवा मद से स्वीकृत हुई?
4. तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी ने जारी की?
5. निर्माण एजेंसी कौन है?
6. ठेका किस ठेकेदार को और किस प्रक्रिया से दिया गया?
7. कार्यादेश क्रमांक और दिनांक क्या है?
8. निर्माण प्रारंभ और पूर्ण होने की निर्धारित तारीख क्या है?
9. तकनीकी निगरानी किस उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री अथवा सक्षम अधिकारी के जिम्मे है?
10. निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट क्यों दिखाई नहीं दे रहा?
11. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? 12. अब तक निर्माण एजेंसी को कितना भुगतान किया जा चुका है?

तहसील मुख्यालय के पास ही पारदर्शिता का सवाल- घुघरी तहसील मुख्यालय में प्रशासनिक कार्यालयों से कुछ ही दूरी पर चल रहे इस निर्माण को लेकर उठे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि यदि सरकारी निर्माण स्थल पर नागरिकों को उसकी लागत, योजना और जिम्मेदार एजेंसी की जानकारी आसानी से नहीं मिलती तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की सार्वजनिक निगरानी को लेकर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

बोर्ड सिर्फ पट्टी नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही का माध्यम- सार्वजनिक धन से बनने वाले भवन में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि कार्य किस स्वीकृति, किस योजना, कितनी लागत और किस एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग यदि स्वीकृति, कार्यादेश, लागत और तकनीकी निगरानी से जुड़े दस्तावेज सामने रखता है तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सकती है।

नेशनल हाईवे पर पुलिस की दबिश, 36.35 लाख का मशरूका जब्त; 9 आरोपी गिरफ्तार/कार्रवाई के घेरे में

बिछिया पुलिस का नाइट ऑपरेशन: पांच पिकअप में ठूंसकर ले जाए जा रहे थे 15 मवेशी



दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। बिछिया पुलिस ने अवैध एवं क्रूरतापूर्वक मवेशी परिवहन के खिलाफ रात में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच पिकअप वाहनों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक, 26-27 सितंबर की दरमियानी रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर सघन वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध पांच पिकअप वाहनों को रोककर जांच की गई, जिसमें कुल 15 मवेशियों का अवैध एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 मवेशियों सहित पांच वाहनों को जब्त किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 36 लाख 35 हजार रुपये बताई गई है। मामले में कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध थाना बिछिया में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कानून की धाराओं में शिकंजा

पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ), मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 तथा संबंधित वाहनों के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/196 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जिन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, उनमें मुकेश ओंगरे, शाहिक पार्ते, अरविन्द डेहरिया, महेन्द्र पार्ते, होरीलाल, विजयकुमार पार्ते, चन्द्रभान देवाकर, सुनील कुमार जोगी एवं अमर खुंते शामिल हैं। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं।

कांजीहाउस में सुरक्षित रखे गए मवेशी

पुलिस द्वारा बरामद किए गए सभी 15 मवेशियों को सुरक्षित रूप से कांजीहाउस बिछिया में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार उनके संरक्षण एवं आगे की वैधानिक प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है।

नाइट चेकिंग में पुलिस टीम की अहम भूमिका

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के निर्देशन, एसडीओपी बिछिया सौरव तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बिछिया रंजीत सिंह सैयाम के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में सउनि कलीराम उइके, प्रधान आरक्षक अनिल मर्सकोले, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र, प्रधान आरक्षक देवराज वाडिवा, प्रधान आरक्षक विवेक दुबे, आरक्षक अमृत मेरावी, आरक्षक नीरज मिश्रा एवं एसएसयू बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध पशु परिवहन, पशु क्रूरता और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नेशनल हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों की निगरानी और वाहन चेकिंग को भी जारी रखने की बात कही गई है।



स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक, मुकेश श्रीवास द्वारा मां रेवा पब्लिकेशन जबलपुर 68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड मुस्कान प्लाजा के पीछे MR-4 रोड उखरी जबलपुर से मुद्रित एवं सिविल लाईन जवाहर वार्ड मंडला से प्रकाशित। प्रधान संपादक-मुकेश श्रीवास, सिविल लाईन, जवाहर वार्ड मंडला । मो. 9406771592, संपादक - प्रहलाद उइके
RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877 (समाचार पत्र के लिये पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार) (न्यायालयीन क्षेत्राधिकार मंडला) Email:- revanchaltimes@gmail.com web-revanchaltimes.in